लखनऊ

बुधवार, 1 अप्रैल, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 218

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"रोज़ाना की छोटी-छोटी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता बनकर सामने आती है।"

TODAY WEATHER

DAY 34° Hi | NIGHT 21° Low

संक्षेप

बंगाल विधानसभा चुनाव: बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की जारी, मैनागुड़ी में बदला उम्मीदवार

कोलकाता। भाजपा ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है और साथ ही मैनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को भी बदल दिया है। भाजपा की इस चौथी सूची में 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी सूची में घोषित एक उम्मीदवार का नाम भी बदला गया है। सूची के अनुसार, दूसरी सूची में घोषित मैनागुड़ी (अनुसूचित जाति) सीट से अब दलिम रॉय भाजपा के उम्मीदवार होंगे। भाजपा की इस नई सूची के अनुसार, सिताई सीट से आशुतोष वर्मा नाटाबाड़ी से गिरिजा शंकर रॉय, बागदा से सोमा ठाकुर, मगराहाट पूर्व से उत्तम कुमार बनिक और फालटा से देबांगशु पांडा को टिकट दिया गया है। वहीं सोनारपुर उत्तर से देबाशीष पाठक, हावड़ा दक्षिण से श्यामल हाती, पंचला सीट से रंजन कुमार पॉल, चंडीपुर से पीयूष कांति दास, गारबेटा से प्रदीप लोढ़ा, मेमारी से मानव गुहा और बाराबनी सीट से अरिजीत रॉय भाजपा उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा गया है। साथ ही, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर क्चछुक्क में शामिल हुए संतोष पाठक को क्चछुक्क ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है।

दिल्ली जा रहे विमान में उठे धुएं से मचा हड़कंप, लखनऊ में कराई इमरजेंसी लैंडिंग; 148 यात्री थे सवार

लखनऊ। लखनऊ में बीती शाम एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह विमान बागडोगरा से नई दिल्ली जा रहा था। जानकारी के अनुसार, उड़ान के दौरान विमान में अचानक धुआं दिखाई देने लगा, जिससे यात्रियों और क्रू में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (रअष्ट) से संपर्क किया और लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही विमान को शाम करीब 5:30 बजे सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया। विमान में कुल 148 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। कुछ यात्रियों को बाद में वैकल्पिक उड़ानों के जरिए दिल्ली भेजा गया। इससे पहले भी नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर विशाखापट्टनम से आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। उस दौरान विमान के इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिलने पर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित किया गया था और रनवे को तुरंत तैयार किया गया। गौरतलब है कि हाल के समय में तकनीकी कारणों से विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियों के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन और नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।

गुजरात को 20,000 करोड़ का तोहफा... पीएम मोदी ने भरी विकास की हुंकार, कांग्रेस को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 20 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी है उन्होंने मंगलवार को राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी ये प्रोजेक्ट यहां के जीवन को एक नई गति देगी वाव-थराद और बनासकांठा के इस क्षेस मेरा काफी लगाव रहा है मैंने मिशन मोड में किया जितना हो सके, उतना गुजरात को हमने आगे बढ़ाया।।

पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरा मन एक और बात से प्रसन्न है जब मैं यहां आया तो पहली बार मेरा विमान सीधे डीसा एयरबेस पर लैंड हुआ डीसा का एयरबेस अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किमी दूरी पर है आप समझ सकते हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी कितना अहम है लेकिन डीसा एयरबेस का काम आज से प्रारंभ नहीं हुआ जब मैं मुख्यमंत्री था तब से मैंने जमीनें एक्वायर की और हम चाहते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत की पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए ये डीसा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

'विश्व अशांति की आग में झुलस रहा···महावीर के संदेश सभी के लिए'

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महावीर जयंती के अवसर पर गुजरात में गांधीनगर के कोबा गांव में नवनिर्मित 'सम्राट संप्रति म्यूजियम' का उद्घाटन किया। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में स्थित इस म्यूजियम का नाम सम्राट संप्रति महाराज (224-215 ईसा पूर्व) के नाम पर रखा गया है। इस दौरान प्रणानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "महावीर जयंती के पावन पर्व पर मुझे इस पवित्र जैन तीर्थ आने का सौभाग्य मिला है। मैं कोबा तीर्थ से सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं।

मगर पता नहीं, दिल्ली में उस समय जो लोग राज करते थे, उन्हें गुजरात के प्रति क्या नफरत थी राष्ट्र की सुरक्षा का ये प्रोजेक्ट भी सालों तक फाइलों में दबा रहा आपने जब मुझे दिल्ली भेजा तो मैंने उन फाइलों को बाहर निकाला और आज उसका परिणाम है कि एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा बेस अब डीसा से जुड़ गया है।

'कांग्रेस को गुजरात से नफरत, देश रहे सावधान'

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने में लगी है विकास का सिलसिला डबल ताकत से लगी है कांग्रेस सरकारों को गुजरात से नफरत थी देश को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए वैश्विक संकट में भी विपक्ष राजनीति कर रहा है गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार कर रही है हमने पूरे गुजरात में, गांव गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ा हाई स्पीड हाइवेज बनाए वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों की सुविधा भी गुजरात को मिल रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मुझे आज यहां दशकों पुराना हाल भी याद रहा है वो दिन कोई नहीं भूल सकता, जब उत्तर गुजरात का नाम आते ही लोगों के मन में एक अलग ही तस्वीर बनती थी सूखा, अकाल आदि को कौन भूल सकता है सघर्ष से भरा ये जीवन, और कांग्रेस सरकार द्वारा हमारी निरंतर उपेक्षा कौन भूल सकता है वो दिन जब कई कई किमी दूर से पानी लाना पड़ता था।

गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी में बनेगा दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र

उन्होंने कहा कि साल 2010 में यानी, आज से 15-16 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए सारंगपुर में देश का पहला सोलर पार्क का काम शुरू करवाया था ये अपने में एक मल्टी टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसने सोलर एनर्जी का मूवमेंट शुरू किया आज गुजरात में जिस प्रकार सोलर एनर्जी का काम हो रहा है जैसे आज ही खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़ी परियोजनाएं शुरू हुई हैं वो दिन दूर नहीं, जब गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा।

असम में गरजे राजनाथ सिंह, बोले–कांग्रेस ने राज्य के साथ हमेशा किया सौतेला व्यवहार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को असम की उपेक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और उस पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। असम के तेजपुर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए, सिंह ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। एनडीए उम्मीदवार और असम गण परिषद के नेता पृथ्वीराज राभा के साथ सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने असम की सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि की प्रशंसा की।

राजनाथ ने कहा कि असम की धरती संस्कृति और प्रकृति दोनों में समृद्ध है। असम की चाय की सुगंध न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में पाई जाती है। यह साहस की भूमि है और महान नायक लचित बोरफुकन की भी। असम के वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आपके इस जज्बे को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी ताकत यहां भाजपा सरकार के गठन को नहीं रोक सकती।

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा असम की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यह संकल्प लिया है कि असम की संस्कृति और पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसीलिए हिमंता के नेतृत्व में दो इंजन वाली सरकार यहां काम कर रही है। असम ने अब भारत में एक विशिष्ट पहचान हासिल कर ली है। कांग्रेस ने हमेशा असम की उपेक्षा की है। यहां असम के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। कांग्रेस के कुशासन के कारण यहां की चर्चा उग्रवाद, गरीबी और अशांति के इर्द-गिर्द घूमती रही। उन्होंने असम के परिदृश्य में आए बदलाव पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि लेकिन अब समय बदल गया है। आज पूरी दुनिया में कोई भी भुखमरी या उग्रवाद की बात नहीं करता। अब यहां विकास की चर्चा होती है, जो भाजपा की बदौलत ही संभव हो पाया है। कांग्रेस शासन के दौरान सीमावर्ती कई गांवों को 'पिछड़े गांव' कहा जाता था, लेकिन हमने उन्हें देश के 'पहले गांव' का दर्जा दिला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर का 30 बार दौरा कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री इस क्षेत्र का दौरा बहुत कम करते थे।

मुझे ही सभी 294 सीटों पर अपना उम्मीदवार समझें... बंगाल के चंद्रकोना में बोलीं ममता

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के चंद्रकोना में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमले बोले। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी बिहार, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अवैध मतदाताओं को बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, बंगाल का अपमान कर रही है। इतना ही नहीं महिलाओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटा रही है।

ममता बनर्जी ने लोगों से कहा, मुझे ही बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार समझें। अगर हम डटे नहीं रहते तो बीजेपी बंगाल की मतदाता सूची से पांच करोड़ नाम हटा देती। जब तक हम सत्ता में हैं बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा और ना ही एनआरसी लागू होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में सत्ता में आने पर बीजेपी मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा देगी।

ममता बनर्जी ने कहा, जब पूरा राज्य असली वोटरों के बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की चिंता में डूबा हुआ था, जब 60 लाख वोटर कानूनी जांच-पड़ताल में फंसे हुए थे और उनके लोकतांत्रिक अधिकार दांव पर लगे थे, ठीक उसी समय पर्दे के पीछे एक साजिश रची जा रही थी। बीजेपी ने एक सोची-समझी साजिश के तहत 30 हजार से ज़्यादा 'फॉर्म 6' के आवेदन जमा किए।

उन्होंने कहा, इसका मकसद बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी-शासित राज्यों से हज़ारों ऐसे वोटरों को चुपके से बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल करवाना था, जो असल में वहां के रहने वाले नहीं हैं। यह एक पूरी तरह से सोच-समझकर किया गया ऑपरेशन था। इसे ऐसे समय पर अंजाम दिया गया था, जब चारों ओर अफरा-तफरी मची हुई थी, ताकि किसी का ध्यान इस पर ना जाए।

सोशल मीडिया पर न्यूज कंटेंट शेयर करने वालों पर भी लागू होगा नियम

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत मध्यस्थों के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की बाध्यताओं का विस्तार करने और ऑनलाइन सामग्री पर विनियामक निगरानी के दायरे को व्यापक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें नॉन-पब्लिशर यूजर्स की ओर से शेयर की गई न्यूज और करंट अफेयर्स शामिल हैं।

मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी है और इसके लिए 14 अप्रैल, 2026 की समय सीमा निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि इन संशोधनों में आईटी नियमों के भाग III की प्रयोज्यता को उन मध्यस्थों पर स्पष्ट करने का प्रस्ताव है, जो ऐसे उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई समाचार और करंट अफेयर्स की सामग्री को होस्ट करते हैं और रजिस्टर्ड पब्लिशर नहीं हैं।

इस कदम से उपयोगकर्ताओं द्वारा समाचार सामग्री के प्रसार को प्रभावी रूप से उस विनियामक ढांचे के दायरे में लाया गया है, जो डिजिटल मीडिया की नैतिकता को नियंत्रित करता है। मसौदे के अनुसार, ये प्रावधान समाचार और करंट अफेयर्स से जुड़ी उस सामग्री पर लागू होंगे, जिसे मध्यस्थों के कंप्यूटर रिसोर्स पर ऐसे यूजर्स द्वारा होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अपडेट या शेयर किया जाता है, जो खुद पब्लिशर नहीं हैं।

ड्राफ्ट में और क्या?

भाग II के तहत एक और अहम प्रस्तावित बदलाव करके एक नए नियम 3(4) को शामिल करना है। यह नियम बिचौलियों के लिए यह साफ तौर पर अनिवार्य कर देगा कि वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपने 'ड्यू डिलिजेंस' (उचित सावधानी) दायित्वों के हिस्से के तौर पर मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों, सलाहों, निर्देशों, SOPs और दिशानिर्देशों का पालन करें। इस ड्राफ्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियम 3(1)(g) और 3(1)(h) के तहत डेटा को सुरक्षित रखने के दायित्व, अन्य लागू कानूनों के तहत जरूरतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभावी रहेंगे।

पीएम मोदी चाहते हैं एलडीएफ की जीत, कन्नूर में राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) जीते। कन्नूर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) एलडीएफ और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त ताकत से लड़ रहा है। यूडीएफ के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे सीपीआई (एम) के दो पूर्व नेता - वी कुन्हीकृष्णन और टी के गोविंदन - भी मंच पर मौजूद थे।

राहुल गांधी ने चुनाव को विचारधाराओं की लड़ाई बताया और वामपंथी और भाजपा के बीच एक असामान्य गठबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है - एक CPI(M) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे की और दूसरी UDF की। पहली बार हम भाजपा और वाम मोर्चे के बीच साझेदारी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि एक वामपंथी दल एक अति दक्षिणपंथी दल के साथ गठबंधन कर रहा है, क्योंकि दोनों की विचारधाराएँ एक-दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं।

गांधी ने कहा कि तो सवाल यह है कि एक वामपंथी दल एक दक्षिणपंथी दल के साथ गठबंधन कैसे कर सकता है? यह एक पहेली की तरह है। उन्होंने पूछा कि इस पहेली के कुछ जवाब मंच पर मौजूद हैं। आज यहाँ CPI(M) के दो दिग्गज नेता मौजूद हैं। वे हमारे मंच पर क्यों बैठे हैं, CPI(M) और मुख्यमंत्री के लिए प्रचार क्यों नहीं कर रहे? गांधी ने आरोप लगाया कि जिसे आज वाम मोर्चा कहा जाता है, वह अब न तो वामपंथी है और न ही मध्यमार्गी। उन्होंने कहा कि दरअसल, वे भाजपा के साथ इसलिए साझेदारी कर रहे हैं क्योंकि वे कॉरपोरेट पार्टियां हैं। वे अब जनता की पार्टियां नहीं रहीं। इसका सबूत अब मंच पर मौजूद है। वामपंथी विचारधारा वाले लोग कांग्रेस के साथ हैं और पार्टी उनका समर्थन कर रही है। केरल में भाजपा के रुख पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्य जगहों पर धर्म और मंदिरों के बारे में अक्सर बोलते हैं, लेकिन केरल में सबरीमाला सोने की चोरी का मुद्दा उठाने से बचते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सबरीमाला सोने की चोरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता शामिल थे और भाजपा पर इस मामले पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।

चिंताजनक

2050 तक 39 अरब टन पहुंचने का अनुमान

तेजी से बढ़ता कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया तेजी से कचरे के ऐसे संकट की ओर बढ़ रही है, जो आने वाले दशकों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक साल 2022 में वैश्विक स्तर पर करीब 26 अरब टन कचरा उत्पन्न हुआ जो 2050 तक बढ़कर 39 अरब टन तक पहुंच सकता है। वहीं, यूएनईपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1 अरब टन भोजन बर्बाद हो रहा है, जिसमें करीब 60 प्रतिशत हिस्सा केवल घरेलू स्तर से आता है।

यूएनईपी आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में उत्पादित कुल भोजन का लगभग पांचवां हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी घरों की है। रेस्टोरेंट, होटल और खुदरा क्षेत्र भी इसमें योगदान देते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार बर्बादी का केंद्र घरेलू स्तर ही है, जो इस संकट को गहरा बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अगर कचरा प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो मनुष्य और प्रकृति को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे कैंसर, दमा और सांस संबंधी बीमारियां फैलती हैं।

यह भूमिगत मिट्टी को दूषित कर खाद्य उत्पादों को प्रभावित करता है, जिसका सीधा संबंध लोगों की सेहत से है। बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों ने जन्म लिया है। इसके बावजूद इस ओर कम से कम ध्यान दिया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कचरे का गलत निपटान भी पर्यावरण के लिए संकट खड़ा कर रहा है। जैविक कचरे के सड़ने से मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन को तेज करती हैं।

अर्थव्यवस्था पर असर

खराब कचरा प्रबंधन का सीधा असर स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार इससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जमीन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पर्यटन और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कचरा प्रबंधन पर निवेश को खर्च नहीं बल्कि दीर्घकालिक बचाव के रूप में देखा जाना चाहिए। श्वि बैंक के मुताबिक कम आय वाले देशों में कचरा प्रबंधन की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। तेजी से बढ़ती आबादी के साथ कचरे की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन उसे संभालने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि अगले 25 वर्षों में इन देशों को कचरा प्रबंधन सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी।

नीतियों के साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझना जरूरी

यूएनईपी और विश्व बैंक दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए बहु-स्तरीय प्रयास जरूरी हैं। जहां सरकारों को कचरा प्रबंधन के ढांचे में निवेश बढ़ाने और प्रभावी नीतियां लागू करने की जरूरत है, वहीं आम लोगों को भी भोजन की बर्बादी कम करने, जरूरत के अनुसार उपभोग करने और कचरे के सही पृथक्करण व पुनर्चक्रण की आदत अपनानी होगी। रिपोर्टों के संकेत स्पष्ट हैं, अगर मौजूदा रुझान नहीं बदले तो आने वाले दशकों में कचरे का संकट वैश्विक स्तर पर और भी गंभीर रूप ले सकता है।

लिएंडर पेस का जोरदार स्मैश, टीएमसी छोड़ भाजपा में हुए शामिल, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाए

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टेनिस के चमकते सितारे लिएंडर पेस ने राजनीति के मैदान में ऐसी एंट्री मारी है जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में लिएंडर पेस का पार्टी में स्वागत किया गया। इस अवसर पर रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बारह वर्षों में खेल और खिलाड़ियों को नई पहचान दी है और अब पेस जैसे दिग्गज का साथ मिलना पार्टी के लिए बेहद अहम है।

हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में कराये जा रहे विधानसभा चुनावों के मौके पर लिएंडर पेस की भाजपा में एंट्री ने चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। खास बात यह है कि हाल ही में उन्होंने कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके पार्टी में आने की अटकलें तेज हो गई थीं।

दिल्ली-मुंबई, लखनऊ से आते थे डॉक्टर, किडनी खरीदने वालों को बताया जाता था रिश्तेदार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कानपुर। कानपुर के किडनी रैकेट के खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमें इसकी जड़ें तक खंगालने में जुट गई हैं। टीम ने आरोपी शिवम को हिरासत में लेकर सोमवार को कई घंटों तक पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया है कि कैसे किडनी खरीद का काला धंधा चलता है।

आरोपी ने बताया कि शक न हो इसके लिए किडनी खरीदने वाले को अपना रिश्तेदार बताया जाता है। उसे गरीब और परिवार का एकमात्र सहारा बताकर कम से कम दाम में सौदा करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जरूरतमंद के परिजन को उसकी गिरती सेहत का हवाला देकर जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम करने के लिए कहा जाता है। बाद में उसे एक डोनर के विषय में बताकर उसकी खर्च करने की हैसियत आकी जाती है। जरूरतमंद के परिजन के तैयार होने पर उसे कई गुना मुनाफा लेकर बेचा दिया जाता है।

कानपुर में अभी कई ऐसे अस्पताल

ऐसे में अब पुलिस उन अस्पतालों के बारे में जानकारी जुटा रही है जिनमें ट्रांसप्लांट किया गया, या इसके बाद मरीज और डोनर को भर्ती कर उनका उपचार किया गया। पुलिस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि सभी अस्पताल बर्रा, नौबस्ता, पनकी और कल्याणपुर जैसे क्षेत्रों में चल रहे हैं।

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इन अस्पतालों में मरीज को गाल ब्लैडर, पथरी या आंतों का रोगी बताकर भर्ती किया जाता था। जहां डोनर को जल्द छुट्टी दे दी जाती। किडनी लेने वाले मरीज को कई माह तक भर्ती रखा जाता। हर अस्पताल में उसके बारे में नई बीमारी बताई जाती है।

आरोपी की जानकारी से पता चला है कि रैकेट में ट्रांसप्लांट मामले से जुड़े रहे कई डॉक्टर और नर्सिंग होम के नाम शामिल हैं। पुलिस की टीमें उसके बताए गए अस्पतालों और डॉक्टरों से पूछताछ कर सच्चाई जानने में जुट गई हैं। चर्चा है कि पुलिस की टीमें पश्चिम बंगाल और हरियाणा भी गई हैं।

बताया जा रहा है कि वहां के युवकों से भी किडनी की खरीद फरोख्त हुई है। मामले में पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लाट के मामले में जितने भी नाम सामने आए हैं, सभी की भूमिका की जांच की जा रही है।

22 साल पहले भी सामने आया था किडनी खरीद का मामला

22 साल पहले भी शहर में किडनी की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया था। इसमें पॉश इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम और उसमें कार्यरत सर्जन का नाम प्रकाश में आया था। आरोप था कि रैकेट में शामिल आर्थिक रूप से कमजोर या किसी अन्य बीमारी का इलाज कराने आए मरीज की उसके संबंधित जांचों के साथ की किडनी की भी जांच की जाती थी।

जिस मरीज को किडनी की जरूरत होती थी, उससे मैच करने पर किडनी निकालकर ट्रांसप्लांट की जाती थी। मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में सीबीसीआईडी ने इस मामले की जांच की थी। इसमें शामिल सर्जन वर्तमान में भी चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

दो महीने पहले बंद हो चुके हॉस्पिटल में भर्ती था डोनर

पुलिस को आवास विकास स्थित आरोही हॉस्पिटल में किडनी डोनर भर्ती मिला है। यह हॉस्पिटल करीब दो माह पहले बंद हो चुका है। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मरीज को हॉस्पिटल के संचालक राजेश के कहने पर भर्ती कराया गया था।

पुलिस को मौके से मरीज के नाम का हॉस्पिटल वाला पर्चा मिला है। किडनी रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने किडनी डोनेट करने वाले और ट्रांसप्लांट कराने वाले की सेहत को देखते हुए उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। देर शाम को एंबुलेंस से पुलिस सुरक्षा में दोनों को अस्पताल भेजा गया था।

दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से आते थे डॉक्टर

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लखनऊ, मुंबई और दिल्ली से स्पेशलिस्ट बुलाए जाते थे। ट्रांसप्लांट की टीम में नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट सर्जन, यूरोलॉजी और ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट होते थे। साथ ही एनेस्थेसिस्ट, डायटीशियन भी टीम का हिस्सा होते थे।

9.5 लाख में किडनी खरीदी, 90 लाख में बेची दलाल और डॉक्टर दंपती समेत दस हिरासत में

कानपुर के कल्याणपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने का मामला प्रकाश में आया है। यहां के एक अस्पताल में उत्तराखंड के युवक से करीब दस लाख रुपये में किडनी खरीदने का सौदा हुआ। किडनी निकलवाने के बाद दलाल ने उसे जरूरतमंद मरीज को 90 लाख रुपये से अधिक में बेच दिया।

अवैध तरीके से की गई किडनी की इस खरीद-फरोख्त का सुराग लगने पर सोमवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अस्पतालों में छापा मारा। पुलिस ने दलाल, अस्पताल संचालक, डॉक्टर दंपती समेत दस लोगों को हिरासत में लिया है।

एक अस्पताल का संबंध आईएमए के एक बड़े पदाधिकारी से बताया जा रहा है। कल्याणपुर के आवास विकास तीन निवासी शिवम अग्रवाल पर आरोप है कि उसने उत्तराखंड के युवक को दस लाख में किडनी बेचने का ऑफर दिया था।

बताया था कि उसके रिश्तेदार को किडनी की जरूरत है। रुपयों की जरूरत के चलते युवक ने हामी भर दी। रावतपुर स्थित एक अस्पताल में किडनी निकाली गई। दलाल शिवम ने इसी अस्पताल में भर्ती मुजफ्फरनगर की महिला मरीज (35) के परिजन को 90 लाख रुपये से अधिक में किडनी बेच दी।

सूत्रों के मुताबिक किडनी बेचने वाले युवक को छह लाख रुपये नकद और 3.5 लाख का चेक दिया। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद दोनों मरीजों को 24 घंटे तक इसी अस्पताल में रखा गया इसके बाद दोनों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

तीन अस्पतालों में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का छापा

किडनी रैकेट की जांच कर रही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार रात तीन अस्पतालों में छापा मारा। इनमें कल्याणपुर आवास विकास एक नंबर स्थित प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, केशवपुरम रोड स्थित आहूजा हॉस्पिटल, पनकी कल्याणपुर रोड स्थित मेडलाइफ हॉस्पिटल शामिल हैं।

टीम ने किडनी संबंधी रोगों के भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी जुटाई। छापे की इस कार्रवाई को किडनी रैकेट से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसमें से कुछ अस्पताल किडनी के अवैध ट्रांसप्लांट मामले में शामिल हो सकते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी खुलकर आरोपियों की गिरफ्तारी या भूमिका के बारे में बोलने से बच रहे हैं।

50 हजार रुपये न मिलने पर की पुलिस से शिकायत

सूत्रों के अनुसार दस लाख में सौदा तय होने के बाद डोनर को सिर्फ 9.5 लाख रुपये दलाल शिवम ने दिए थे। 50 हजार के लिए शिवम उसे टरका रहा था। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की। पुलिस ने जांच की तो किडनी रैकेट की परतें खुलती चली गईं। देर रात क्राइम ब्रांच ने युवक के बताए दोनों अस्पतालों में छापा मारा। जांच में वहां उसके भर्ती होने के सबूत मिले हैं।

क्राइम ब्रांच ने दोनों हॉस्पिटल के संचालक, डॉक्टर दंपती और दलाल शिवम को हिरासत में लिया। वहीं, किडनी लेने वाली मरीज को भी आवास विकास के एक अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया था। पुलिस ने उस हॉस्पिटल में भी जांच की। वहां से पांच अन्य लोगों को उठाकर पूछताछ की जा रही है।

पीड़ित महिला की जमीन पर दबंगों की नजर

सुल्तानपुर। जिले के कादीपुर तहसील के थाना करौदीकला के अन्तर्गत कटघर पूरे चौहान पंडित का पुरवा के रहने वाली मनराजी उम्र 75 बर्ष पत्नी सभा उपाध्याय से जुड़ा हुआ है। पीड़ित महिला वृद्धि अवस्था में चलने फिरने में मजबूर हैं । इसी बात का फायदा उठाकर विपक्षी गणों ने कृष्ण कुमार पुत्र राम सुरेमन, सुरेमन सुत ठाकुर दीन, बब्लू उर्फ सच्चिदानंद व बब्लू उर्फ कृष्णा नन्द, के द्वारा जबरन पीड़ित महिला के चक में चक मार्ग बना रहे थे, पीड़ित महिला के बार बार मना करने पर नहीं माने और जेसीबी मशीन बुलाकर पेड़ पौधे को उजाड़ दिया है लाठी डंडों लेकर पीड़ित महिला के साथ मार पीट व गाली गलौज करने लगे। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस के सामने गाली गलौज करने लगे तो शासन व प्रशासन का को अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में नियंत्रण रखते उसकी धज्जियां उड़ाते हैं।

एडीओ की पेंशन वृद्धि मामले में लापरवाही पर डीपीआरओ सस्पेंड

आर्यावर्त संवाददाता

एटा। अलीगंज क्षेत्र निवासी एडीओ पंचायत ने वर्ष 2009 को पेंशन वृद्धि के लिए राज्य लोक सेवा आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

नोशनल प्रोन्नति वेतन एवं पेंशन को लेकर लगातार शिकायतों के बाद एडीओ पंचायत को वेतन का लाभ मिल गया, मगर 17 साल बीत जाने के बाद भी पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं मिला। इसमें डीपीआरओ को दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें पंचायती राज निदेशालय से सम्बद्ध किया गया है। अलीगंज विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी रूपलाल को नोशनल प्रोन्नति वेतन एवं पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। इसे लेकर उन्होंने वर्ष 2009 में राज्य लोक सेवा आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर आयोग ने वेतन एवं पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश देते हुए वर्ष 2010 को पेंशन निदेशालय मामला भेज दिया। इस पर 2014 में वेतन एवं पेंशन निर्धारित करने को पंचायत निदेशक को आदेशित किया गया। इस पर कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ तो मिल गया, मगर पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सका। जबकि दस डीपीआरओ का जिले से तबादला होता रहा। हक की लड़ाई लड़ते हुए एडीओ पंचायत की वर्ष 2020 में मृत्यु भी हो गई। इस तरह से कर्मचारी की समस्या समाधान में लापरवाही मानते हुए डीपीआरओ मुहम्मद राशिद को निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रकरण की जांच भी शुरू कराई है। जिसकी शासन ने एक माह में रिपोर्ट मांगी है।

यूपीपीसीएस में सिलेक्शन होने पर भगवान के सामने फूट-फूटकर रोए आनंद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-2024 परीक्षा के परिणाम में नायब तहसीलदार पद पर चयन की सूचना मिलने पर आनंद राज सिंह भावुक हो गए। आनंद सीधे हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां भगवान के चरणों में माथा टेकते हुए वह फूट-फूटकर रो पड़े।

उनकी आंखों से छलकते आंसुओं में वर्षों की मेहनत, संघर्ष और सपनों के साकार होने की खुशी साफ झलक रही थी। इस भावुक पल का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है और लोग उनकी सफलता को प्रेरणादायक बता रहे हैं।

सोनभद्र जिले की घोरावल तहसील के केवली गांव निवासी आनंद राज सिंह ने यूपी पीसीएस परीक्षा में अपने दूसरे प्रयास में नायब तहसीलदार पद पर चयन सुनिश्चित किया। आनंद पिछले चार वर्षों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे थे। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने कठिन परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर यह मुकाम हासिल किया। आनंद के पिता आत्मानंद सिंह झूंसी स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी में कार्यरत हैं। साधारण परिवार से आने वाले आनंद की सफलता ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गांव में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आनंद की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। आनंद ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के आशीर्वाद, परिवार के सहयोग और निरंतर मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि कई बार कठिनाइयां आईं, लेकिन लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाया। मंदिर में रो पड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि यह आंसू संघर्ष के उन वर्षों की याद और सफलता की खुशी के थे, जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है।

खनिज विभाग की छापेमारी में चित्रकूट में फर्जी रवन्ना रैकेट का खुलासा, दुकान पर बनते मिले ; एक गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

चित्रकूट। अवैध ढंग से खनन के साथ फर्जी रवन्ना बना मौरंग-गिट्टी परिवहन कर राजस्व को चूना लगाने वाले रैकेट का राजफाश हुआ है। भरतकूप स्थित दुकान में बांदा जिले की खदानों के नाम से जारी रवन्ना की कंप्यूटराइज्ड फर्जी प्रतियां तैयार कर चित्रकूट में धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही थीं।

मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार कर 25 फर्जी रवन्ना, प्रिंटर, लैपटाप व अन्य सामग्री बरामद की गई है। दो आरोपित मौके से भाग निकले। प्रारंभिक जांच में लाखों रुपये के राजस्व के नुकसान की आशंका जताई गई है।

खनिज विभाग की छापेमारी में एक गिरफ्तार, लैपटॉप, प्रिंटर व सामग्री बरामद

झांसी-मीरजापुर हाईवे किनारे भरतकूप में भारत पेट्रोल पंप के पास स्थित दुकान पर सोमवार को खनिज व पुलिस विभाग की टीम ने छापा मारा। संचालक अंदर से दरवाजा बंद कर पीछे की ओर से भाग निकला। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर भरथौल निवासी योगेंद्र कुमार को पकड़ लिया। उसने रैकेट के अन्य दो साथियों के नाम भी उगल दिए। बरामद कागजात बांदा के नरैनी क्षेत्र के खदान पट्टाधारकों के नाम पर जारी बताए गए, जिन्हें यहां अवैध परिवहन में खपाया जा रहा था।

चित्रकूट में दुकान पर बनते मिले फर्जी रवन्ना, तीन के विरुद्ध रिपोर्ट

खनिज इंस्पेक्टर मंटू सिंह ने बताया कि यह संगठित तरीके से चल रहा फर्जीवाड़ा है और काफी समय से सक्रिय था। इससे जिले के राजस्व को नुकसान हुआ है। कड़ियां बांदा से जुड़ रही हैं, इसलिए वहां के खनिज विभाग से भी जानकारी ली जा रही है।

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ उप्र उपखनिज नियमावली, खनन एवं खनिज विकास का विनियमन, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान निवारण व धोखाधड़ी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो फरार हैं।

अवैध गोमांस कारोबार का खुलासा, इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

सुलतानपुर। गोसाईंगंज थाना क्षेत्र में चर्चित इंस्पेक्टर राम आशीष उपाध्याय के संरक्षण में महीनों से अवैध गोमांस का कारोबार चल रहा था। शनिवार रात्रि हिंदू संगठनों ने थाना क्षेत्र के राजापुर में इस अवैध धंधे को पकड़ लिया। मौके से कुंतल भर गोमांस, चापड़, तराजू व एक चार पहिया वाहन बरामद किया गया। वहीं, अवैध धंधे से जुड़े दो आरोपियों को हिंदू संगठन के लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभियोग पंजीकृत करने में पुलिस द्वारा खेल किए जाने का आरोप है। कोर्ट ने आठ आरोपियों की रिमांड को खारिज कर दिया था। कोर्ट से छूटने के बाद गोमांस तस्करों ने संगठन के लोगों को धमकी दी। इसके बाद हिंदू संगठन ने पुलिस कप्तान चारू निगम से शिकायत की। जांच में दोषी मिलने पर चर्चित इंस्पेक्टर राम आशीष उपाध्याय समेत एक चौकी इंचार्ज व एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया।

बलिया में फर्जी अंकपत्र के सहारे बीस साल नौकरी करने वाले प्रधानाध्यापक बर्खास्त

आर्यावर्त संवाददाता

बलिया। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी अंकपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले एक प्रधानाध्यापक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वह लगभग 20 साल से नौकरी कर रहे थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए नियुक्ति को प्रारंभ से ही शून्य मानते हुए संबंधित शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और अब तक दिए गए वेतन की वसूली के निर्देश भी दिए हैं।

यह मामला प्राथमिक विद्यालय नोनियापुरा (बाछापार), शिक्षा क्षेत्र पंदह से जुड़ा है। यहां तैनात प्रधानाध्यापक ध्रुवनाथ यादव, गौरी सिकंदरपुर के निवासी हैं। उनके खिलाफ दिनेश कुमार यादव निवासी गौरी ने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ से शपथ पत्र देकर शिकायत की थी। इस पर संबंधित शिक्षक के शैक्षिणिक अभिलेखों की जांच कराई गई। जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने स्नातक की अंकपत्र में हेराफेरी कर अधिक अंक दर्शाए थे। जहां वास्तविक अंक 445 पाए गए, वहीं प्रस्तुत अभिलेख में 504 अंक अंकित थे। इस तरह 59 अंकों की बढ़ोतरी कर नौकरी प्राप्त की गई। शिकायत के आधार पर संबंधित महाविद्यालय श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर के प्राचार्य से सत्यापन कराया गया, जिसमें अंकपत्र फर्जी पाया गया। संबंधित शिक्षक के द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर भी गलत विवरण अपलोड किए जाने की पुष्टि हुई। शिक्षक की जांच के लिए विभाग ने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन जवाब संतोषजनक न मिलने पर कठोर कार्रवाई की गई। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त नियुक्ति अवैध है, इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अब तक दिए गए वेतन व भत्तों का आकलन कर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी को दिया गया है कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि यदि सत्यापन में किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बरेली में दो बच्चों की मां पहले प्रयास में बनीं अफसर, संविदाकर्मी ने भी लहराया परचम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। बरेली जिले के कई होनहारों ने यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा में कामयाबी का परचम लहराया है। दो बच्चों की मां 34 वर्षीय आकांक्षा ने पहले प्रयास में कामयाबी पाई है। 42 वर्षीय संविदा कर्मचारी ने तीसरे प्रयास में सफलता पाई। किसान के बेटे का चयन असिस्टेंट कमिश्नर पद पर हुआ है। जिले के कई अन्य युवाओं का चयन नायब तहसीलदार समेत अन्य पदों पर हुआ है। इसमें किसी ने ऑनलाइन तो कुछ ने ऑफलाइन पढ़ाई कर परचम लहराया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले यूपीएससी को लक्ष्य बनाया, कामयाबी नहीं मिली तो यूपीपीएससी पर फोकस किया।

पति और ससुर के प्रोत्साहन से मिली कामयाबी

दुर्गा नगर की 34 वर्षीय आकांक्षा सक्सेना वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक हैं। उनका चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। वह बताती हैं कि वर्ष 2009 में 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। तब वह स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा थीं। इसके बाद ससुर योगेंद्र कुमार कंचन के सहयोग से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की, फिर बीएड किया। वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी में ससुर के लापता हो जाने के बाद पति शिवम सक्सेना के सहयोग से उन्होंने अपनी पढ़ाई व गृहस्थी सुचारु रूप से चलाई। इस बीच उनके दो बच्चे भी हुए। वह बताती हैं कि उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली, लेकिन लखनऊ के एक संस्थान से टेस्ट सीरीज पूरी की। उपासना के पिता धर्म सिंह मार्छाल मुरादाबाद में एडिशनल एसपी के पद पर कार्यरत हैं।

यूपीएससी में मिली निराशा, पीसीएस में कामयाबी

सनराइज एन्क्लेव की 26 वर्षीय उपासना मार्छाल का चयन खंड विकास अधिकारी पद पर हुआ है। वह बताती हैं कि यूपीएससी में सफलता नहीं मिली तो परिवार वालों ने पीसीएस की तैयारी करने का सुझाव दिया। इसके बाद दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। उनकी 12वीं तक की पढ़ाई बरेली में हुई। इसके बाद डीयू से बीटेक किया। बीटेक के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान सिविल सेवा में जाने का मन बनाया। इसके बाद वर्ष 2021 से तैयारी शुरू कर दी। वह बताती हैं कि उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली, लेकिन लखनऊ के एक संस्थान से टेस्ट सीरीज पूरी की। उपासना के पिता धर्म सिंह मार्छाल मुरादाबाद में एडिशनल एसपी के पद पर कार्यरत हैं।

शैलेंद्र बने असिस्टेंट कमिश्नर

गांव गुलड़िया अरिल के किसान रूम सिंह के बेटे शैलेंद्र कुमार ने प्रथम प्रयास में यूपीपीएससी परीक्षा में कामयाबी का परचम लहराया। उनका चयन असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर) पद पर हुआ है। शैलेंद्र ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा चंदौसी से प्राप्त की। इसके बाद बीएससी किया। डायट फरीदपुर से डिप्लोमा किया। मां विमलेश देवा पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शैलेंद्र को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। शैलेंद्र के बड़े भाई पुलिस विभाग में कार्यरत हैं।

नौ साल का श्रम हुआ सार्थक

इज्जतनगर की अशरफ खां छावनी निवासी अतहर जमाल खान का चयन पंचायती राज विभाग में कार्य अधिकारी पद पर हुआ है। अतहर ने बताया कि उन्होंने 2015 में तैयारी शुरू की थी, लेकिन शुरुआत में जानकारी का अभाव फिर कोरोना की वजह से समय लगा। इस दौरान यूपीएससी की परीक्षा भी दी। कामयाबी नहीं मिली तो पीसीएस परीक्षा को लक्ष्य बनाया। बीते वर्षों में दो-तीन बार साक्षात्कार तक पहुंचे लेकिन सफलता इस बार मिली। वह बताते हैं कि संघर्ष के दौरान परिवार का पूरा सहयोग रहा।

कुशाग्र बने नायब तहसीलदार

विद्युत निगम के चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश के बेटे कुशाग्र प्रकाश का चयन नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। वर्क फ्रॉम होम के साथ पीसीएस की तैयारी करते हुए उन्होंने पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की है। मूल रूप से मेरठ के रहने वाले 25 वर्षीय कुशाग्र ने बताया कि उनकी स्कूली शिक्षा मेरठ से हुई। इसके बाद आईआईटी धनबाद से इंजीनियरिंग की। फिर सिविल सेवा की तैयारी में जुटे थे।

तीसरे प्रयास में प्राप्त की सफलता

बहेड़ी के सिमरा भोगपुर निवासी 42 वर्षीय सुरेश बाबू ने तीसरे प्रयास में कामयाबी पाई है। इससे पहले दो बार वह साक्षात्कार तक पहुंचे थे। वह वर्ष 2011 से बदायूं में संविदा पर मूकबधिर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कोरोना के दौरान वर्ष 2021 में भाई की मृत्यु से परिवार को आर्थिक व भावनात्मक रूप से बड़ा झटका लगा था। इसके बाद सुरेश ने पीसीएस परीक्षा देने की ठानी। शुरुआती तैयारी अभ्युदय कोचिंग से की। इसके बाद वह अपने गुरु एसपी शर्मा की देखरेख में तैयारी करते रहे। वह 2025 की परीक्षा भी दे रहे हैं।

पत्रकार एसोसिएशन की वार्षिक बैठक एवं होली मिलन कार्यक्रम संपन्न

सुल्तानपुर। संगठन पत्रकार हितों के कार्य करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। संगठन के सहयोग से पत्रकार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने में हमारा संगठन पीछे नहीं है। पत्रकारों को तथ्य परक खबरों का ही चयन करना चाहिए, बिना किसी भय, राग द्वेष के खबरों का प्रकाशन करना चाहिए। पत्रकारों की समस्याओं के विरुद्ध लिए हमारा संगठन हमेशा संघर्ष के लिए तत्पर है। उक्त बातें पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ0अवधेश शुक्ला ने प्रेस क्लब में आयोजित वार्षिक बैठक में उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। बैठक को जिलाध्यक्ष अमेठी रमन पांडे, तहसील बल्दीराय अध्यक्ष पीर मोहम्मद, इम्तियाज खान, नितिन विश्वास ने भी संबोधित किया। बैठक के बाद होली मिलन कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। गुझिया खाकर एक दूसरे के गले मिले।

योगी सरकार में एक्सपोर्ट को मिली रफ्तार, नवंबर 2025-26 तक यूपी के निर्यात ने पार किया 1.31 लाख करोड़ का आंकड़ा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निर्यात के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार की उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन नीतियों के चलते प्रदेश का निर्यात न केवल दोगुना हुआ है, बल्कि वैश्विक बाजार में 'मेड इन यूपी' की मजबूत पहचान भी बनी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से नवंबर तक प्रदेश का कुल निर्यात ₹1,31,328 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹1,18,223.91 करोड़ की तुलना में 11.08 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश का निर्यात ₹86 हजार करोड़ था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर ₹1.86 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए 2025-26 में इस रिकॉर्ड को भी पार करने की संभावना जताई गई है।

योगी सरकार की नीतियों से निर्यात क्षेत्र में यूपी की मजबूत पकड़

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनाई गई दूरदर्शी नीतियों, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश के अनुकूल माहौल और निर्यातकों को दी जा रही सुविधाओं ने प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से देश के अग्रणी निर्यातक राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

'लोकल टू ग्लोबल' की सोच को साकार करते हुए प्रदेश के उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। आने वाले समय में यह रफ्तार और तेज होने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश न केवल निर्यात के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को भी सशक्त आधार प्रदान करेगा।

आईटी/आईटीईएस निर्यात ₹82 हजार करोड़ के पार

आईटी और आईटीईएस सेक्टर में भी योगी सरकार की नीतियों का स्पष्ट असर देखने को मिला है। वर्ष 2015 में जहां सूचना प्रौद्योगिकी/आईटीईएस निर्यात ₹15 हजार करोड़ था, वह 2024-25 में बढ़कर ₹82 हजार करोड़ से अधिक हो गया है। यह सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार और निवेश अनुकूल माहौल का परिणाम है।

प्रदेश सरकार 'लोकल टू ग्लोबल' की अवधारणा को मजबूती देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के 77 उत्पादों को जीआई (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) पंजीकरण प्राप्त हो चुका है, जबकि 152 अन्य उत्पाद इस दिशा में अग्रसर हैं। इससे पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान और मूल्य दोनों मिल रहे हैं।

बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर

निर्यात को नई गति देने के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में स्थापित अत्याधुनिक एक्सपो मार्ट न केवल प्रदेश के निर्यातकों को वैश्विक बाजार से सीधे जोड़ रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख ट्रेड हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

इसी क्रम में भदोही में विकसित 'भदोही कार्पेट बाजार (एक्सपो मार्ट)' पारंपरिक कालीन उद्योग को नई ऊर्जा दे रहा है। यह पहल न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को वैश्विक मंच प्रदान कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी दिला रही है।

आरडीएसओ लखनऊ में मानव तस्करी रोकथाम पर कार्यशाला आयोजित, 250 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ), लखनऊ के ऑडिटोरियम में मानव तस्करी (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) विषय पर रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यशाला रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत आयोजित की गई।कार्यशाला की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया किशोर राहतकर रहीं। विशिष्ट अतिथियों में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ बबीता सिंह चौहान, पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त सत्य प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ गौरव अग्रवाल, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) नीतू, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आरडीएसओ लखनऊ अरुण कुमार चौरसिया तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के डिप्टी डायरेक्टर राम अवतार सिंह उपस्थित रहे। कार्यशाला का आयोजन एवं संचालन वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ अरुण त्रिपाठी द्वारा किया गया।कार्यशाला में कानूनी विशेषज्ञ एवं शक्ति वाहिनी के सह-संस्थापक निशिकांत तथा रमददद फाउंडेशन के संस्थापक राजेश मणि ने राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के साथ मानव तस्करी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इस कार्यशाला में जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी के असिस्टेंट कमांडेंट प्रोबेशनर्स, विभिन्न जोनल रेलवे से आए 22 सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ एवं जीआरपी के अधिकारी एवं कर्मचारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सदस्य, पूर्वोत्तर रेलवे के परिचालन एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारी तथा स्टेकहोल्डर्स (कुली एवं वेंडर) सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया।मुख्य अतिथि विजया किशोर राहतकर ने अपने संबोधन में कहा कि रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच बेहतर समन्वय ही रेलवे के माध्यम से होने वाली मानव तस्करी को जड़ से समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों के साथ-साथ जमीनी स्तर पर कार्यरत रेल कर्मियों, जैसे कुली और वेंडर, की सजगता को अत्यंत आवश्यक बताया।कार्यशाला में 'सॉफ्ट टारगेट' की पहचान एवं निगरानी, कुली एवं वेंडर्स की भूमिका, 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते', 'ऑपरेशन आहट', 'ऑपरेशन मेरी सहेली' और 'ऑपरेशन मातृशक्ति' सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों, अंतर-विभागीय समन्वय, आरपीएफ एवं एनसीडब्ल्यू के एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन तथा तकनीकी संसाधनों और हेल्पलाइन के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।कार्यशाला के दौरान आरपीएफ एवं जीआरपी के समन्वय से गठित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बल सदस्यों को मुख्य सुरक्षा आयुक्त सत्य प्रकाश द्वारा सम्मानित किया गया।

पुलिस मॉडर्न स्कूल में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ, पुलिस परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (वामा सारथी) के संयुक्त प्रयासों से पुलिस लाइन्स स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज की गई। वामा सारथी (लखनऊ चैप्टर) की अध्यक्षा डॉ. श्वेता सेंगर की पहल पर विद्यालय में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया।वामा सारथी की विशेष पहल तथा रोटरी क्लब ट्रांस गोमती के सहयोग से विद्यालय की कक्षा 8 से 10 तक के छात्र-छात्राओं के लिए सीबीएसई आधारित डिजिटल स्मार्ट क्लास स्थापित की गई है। इस तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी अब कठिन विषयों को ऑडियो-विजुअल माध्यम से अधिक सरलता से समझ सकेंगे। इस अवसर पर डॉ. श्वेता सेंगर ने कहा कि आधुनिक समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पुलिस परिवारों के बच्चों का अधिकार है और यह स्मार्ट क्लास उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।शिक्षा के साथ-साथ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विद्यालय परिसर में अपोलो हॉस्पिटल्स के सहयोग से एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस कर्मियों के परिवारों और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों और स्टाफ की सुविधा के लिए विद्यालय परिसर में एक नया वाटर कूलर भी स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस अवसर पर वामा सारथी के पदाधिकारी, रोटरी क्लब के सदस्य, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

पर्यटन और संस्कृति परियोजनाओं में 96 प्रतिशत बजट स्वीकृत, यूपी को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने अपनी प्रगति और योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारना प्राथमिकता है, ताकि प्रदेश में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को और गति मिल सके। इससे पहले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक कर वित्तीय स्वीकृतियों, आवंटन और व्यय की स्थिति का आकलन करते हुए पारदर्शी और समयबद्ध बजट उपयोग के निर्देश दिए थे।पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 1801.30 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के सापेक्ष 1729.22 करोड़ रुपये, यानी

लगभग 96 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं संस्कृति विभाग के बजट खर्च के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कुल 200 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के सापेक्ष 186.96 करोड़ रुपये, यानी लगभग 93.48 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों में बजट का उपयोग पारदर्शिता, समयबद्धता और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल परियोजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आम जनता और पर्यटकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी और विश्वस्तरीय परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इनमें अल्पज्ञात पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का समग्र विकास, लखनऊ में प्रस्तावित अत्याधुनिक नौसेना संग्रहालय, अयोध्या में लव-कुश पार्क, श्रद्धा, रामायण वैक्स म्यूजियम तथा अत्याधुनिक रामकथा संग्रहालय जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त फिरोजाबाद में ग्लास म्यूजियम और उत्तर भारत का पहला आधुनिक आर्य गुरुकुल म्यूजियम भी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नए आयाम देने का कार्य करेंगे।मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसके लिए पर्यटन स्थलों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होकर गुजरने वाले प्रमुख राजमार्गों के किनारे आधुनिक वे-साइड एमेनिटीज विकसित करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मिले 1010 आवेदन, मई से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होगा बस संचालन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के हजारों गांवों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण मार्गों पर मिनी बसों के संचालन की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित सभी 20 क्षेत्रों से 28 मार्च 2026 तक कुल 1010 आवेदन प्राप्त हुए हैं।यह जानकारी परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने देते हुए बताया कि अप्रैल माह में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि मई से ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी बसों का संचालन शुरू कराया जा सके। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों में प्रयागराज क्षेत्र से सर्वाधिक 118, सहारनपुर से 144, वाराणसी से 90, अलीगढ़ से 87, मुरादाबाद से 78 तथा झांसी क्षेत्र से 59 आवेदन शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ से 42, अयोध्या से

20, आगरा से 38, आजमगढ़ से 43, इटावा से 27, कानपुर से 24, गाजियाबाद से 37, गोरखपुर से 40, चित्रकूट-बांदा से 39, देवीपाटन से 25, नोएडा से 12, बरेली से 41, मेरठ से 36 और हरदोई क्षेत्र से 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं।परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना से जुड़े सभी कार्यों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 59,163 ग्राम पंचायतों को परिवहन सुविधा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। लगभग 12,200 गांवों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी मिनी बसों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है।उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना ग्रामीण मार्गों पर 15 से 28 सीट क्षमता वाली निजी मिनी बसों के संचालन की है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत को सुगम और सस्ती परिवहन सेवा से जोड़ना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को विकास खंड, तहसील और जनपद मुख्यालय से सीधे जोड़ा जा सके।दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और अब तक परिवहन सुविधा से वंचित ग्राम पंचायतों को मुख्य धारा से जोड़ना और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक परिवहन सेवा पहुंचाना इस योजना का मुख्य आधार है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण जनता को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सुरक्षित और सीधी पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ उन ग्रामीण मार्गों पर भी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

2 अप्रैल से शुरू होगी दलहन-तिलहन की खरीद, किसानों को एमएसपी पर मिलेगा लाभकारी मूल्य : सूर्य प्रताप शाही

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेसवार्ता में रबी सीजन 2026-27 के लिए दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीद को लेकर विस्तृत रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रभावी व्यवस्था की गई है।कृषि मंत्री ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के अनुसार प्रदेश में चना, मसूर, सरसों एवं तूर (अरहर) की खरीद 2 अप्रैल से 30 जून 2026 तक की अवधि में की जाएगी। इस दौरान चना का एमएसपी 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों

6200 रुपये प्रति क्विंटल तथा तूर 8000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि चना के लिए 2.24 लाख मीट्रिक टन, मसूर के लिए 6.77 लाख मीट्रिक टन, सरसों के लिए 5.30 लाख मीट्रिक टन तथा तूर के लिए 1.14 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।उन्होंने बताया कि क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी क्रय केंद्रों पर आधार-सक्षम पीओएस मशीनें स्थापित की गई हैं, जिससे किसानों की पहचान सुनिश्चित करते हुए डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। इस वर्ष 190 से अधिक क्रय केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जबकि राज्य स्तरीय एजेंसियां भी अपने स्तर पर अतिरिक्त केंद्र संचालित करेंगी।कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग द्वारा लगभग 5700 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि विभिन्न योजनाओं पर व्यय की गई, जो एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधारात्मक प्रावधान लागू कर राज्य को 303 करोड़ रुपये की बचत भी हुई है।उन्होंने बताया कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए बीज वितरण योजनाओं के तहत 11.25 लाख किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया गया, जबकि 12.73 लाख किसानों को 54,847 क्विंटल बीज निःशुल्क वितरित किया गया। जायद फसलों के प्रोत्साहन हेतु इस वर्ष 31,950 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया, जिसमें मूंगफली, उड़द एवं मूंग शामिल हैं। प्रेसवार्ता में यह भी बताया गया कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में राज्य में 25.41 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उर्वरकों का वितरण पीओएस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनी हुई है।कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में "भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क" की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 50.84 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। यह सीड पार्क प्रदेश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, फसलों की उचित कीमत सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन शुरू, विश्व शांति और सहअस्तित्व पर हो रहा मंथन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्थल से विश्व शांति का संदेश देने वाला अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2026 मंगलवार से प्रारंभ हो गया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में देश-विदेश से आए बौद्ध भिक्षु, संत, विद्वान, नीति-निर्माता और युवा एक मंच पर एकत्र हुए हैं। सम्मेलन में भगवान बुद्ध की करुणा, शांति और शिक्षाओं की वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में प्रासंगिकता पर गहन मंथन किया जा रहा है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अनिश्चितता का वातावरण है, ऐसे समय में भगवान बुद्ध के जीवन संदेश मानवता के लिए सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि

कुशीनगर में आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वैश्विक स्तर पर शांति, सहअस्तित्व और आपसी समझ को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बुद्धा लाइफ गैलरी का उद्घाटन भी किया गया। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने अतिथियों का स्वागत किया। आरआईएस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंकज वशिष्ठ ने बौद्ध दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे। सम्मेलन के दौरान 'बुद्धाज कुशीनगर' विषय पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।औपचारिक उद्घाटन के बाद शांति उपवन में 'धम्म, संवाद और विकास' विषय पर छात्र चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी कलाकृतियों के माध्यम से बौद्ध मूल्यों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। इसके बाद आयोजित शैक्षणिक सत्रों में भिक्षुओं के दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म, बौद्ध-जैन समागम तथा समकालीन समाज में बौद्ध विचारधारा की प्रासंगिकता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।सम्मेलन के पहले दिन दक्षिण कोरिया, लाओस, जापान और भारत के विशेषज्ञों ने 'बौद्ध धर्म-धम्म, संवाद और विकास' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लेते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बौद्ध मूल्यों की उपयोगिता और समावेशी समाज के निर्माण में उनकी भूमिका पर विचार साझा किए।सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 'विकसित कुशीनगर 2047: आगे की राह', 'कुशीनगर को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित करने की संभावनाएं' तथा 'निवेश के अवसर एवं राज्य नीतियों की भूमिका' शामिल हैं। इसके साथ ही छात्र वाद-विवाद प्रतियोगिता, पर्यटन शिक्षा से संबंधित अकादमिक सत्र और महापरिनिर्वाण हेरिटेज कॉरिडोर के मानचित्र पर पैनल चर्चा भी आयोजित होगी। शाम को भोजपुरी नाइट कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक रितेश पांडेय अपनी प्रस्तुति देंगे।तीसरे दिन 'युद्ध के समय में बुद्ध की प्रासंगिकता', 'बौद्ध धर्म में अंतरराज्यीय समन्वय' तथा 'कुशीनगर के लिए धम्म आधारित विजन-2030' जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों में लागू होगा 'प्रोजेक्ट प्रवीण', 3447 विद्यार्थियों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और कौशल विकास को एकीकृत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' लागू किया जाएगा, जिसके तहत 3447 विद्यार्थियों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।यह पहल व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देशन में आगे बढ़ाई जा रही है। 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के अंतर्गत विद्यार्थियों को आईटी, आईटीईएस, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब तक यह कार्यक्रम केवल सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में संचालित था, लेकिन अटल आवासीय विद्यालयों को इसमें शामिल किए जाने से इसका दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे।मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर कराए गए सर्वे के आधार पर इन विद्यालयों का चयन किया गया है। सर्वे के अनुसार आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, बांदा, गोंडा, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बुलंदशहर, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद स्थित 18 अटल आवासीय विद्यालयों के कुल 3447 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए पात्र पाया गया है। विद्यार्थियों की विशेष रुचि आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एपरेल सेक्टर में देखी गई है।अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत संचालित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिकों, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। कक्षा 6 से 12 तक संचालित इन विद्यालयों में अब आधुनिक कौशल प्रशिक्षण भी जोड़ा जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बल मिलेगा।मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि 'प्रोजेक्ट प्रवीण' 210 घंटे का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें आईटी, ब्यूटी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स तथा इंडस्ट्रियल विजिट भी शामिल हैं। इसके साथ ही एआई आधारित मॉड्यूल को भी जोड़ा गया है।

ईरान अमेरिका युद्ध से राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मुश्किलों से घिरे, यूएस कांग्रेस में आ सकता है नॉनकॉनफिडेंस मोशन

28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईरान इस स्तर का रिटेलियट करेगा । लेकिन युद्ध एक महीने बाद भी चल रहा है। इजरायल के कहने पर शुरू हुए इस युद्ध ने पूरी दुनिया को विशेषकर मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया को ऊर्जा जरूरतों की दृष्टि से संकट में डाल दिया है। यदिप ईरान भी बुरी तरह नष्ट हो रहा है। लेकिन यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब आदि देशों में भी यूएस बेस पर तथा शहरी आवादी, एरोड्रम पर बहुत नुक्सान हुआ है। लेकिन अब डॉनल्ड ट्रंप अपने घर पर राजनीत में उलझ गए हैं। डेमोक्रेटिक पूरे मामले को कांग्रेस में करना चाहते हैं और रिचर्ड निक्सन जैसा करना चाहते हैं क्योंकि वाटरगेट कांड 1972 के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।

उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, तुलसी गैबार्ड,सहित ट्रंप के साथी अब इस युद्ध के खिलाफ है।तुलसी गैबार्ड ने कहा है कि 17 लाख करोड़ रुपए अब तक युद्ध में खर्च हो चुके हैं और पेंटागन 200 बिलियन डॉलर की मांग कर रहा है। तुलसी गैबार्ड अमेरकन सरकार की इंटेलीजेंस प्रमुख है।

दूसरी ओर ईरान ने पूरी दुनिया का 20 परसेंट तेल टैंकरों को हॉर्मूज समुद्री क्षेत्र में रोक दिया है।केवल चाइना, भारत,के तेल टैंकरों, गैस टैंकरों को हॉर्मूज समुद्री क्षेत्र से गुजरने की परमीशन है।

डॉनल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे है कि नाटो देश अपनी समुद्री जहाज,सेना हॉर्मूज समुद्री क्षेत्र को खुलवाने में मदद करे लेकिन इटली फ्रांस, जर्मनी,स्पेन, ब्रिटिश ने साफ इनकार कर दिया है।स्पेन ने तो युद्ध को पाप बताया है।

इजरायल मौके का फायदा उठा कर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हिज्बुल्लाह,हमास, बेरुत,लेबनान पर हमला कर खासा नुक़सान पहुंचा दिया है।रूस और चाइना ईरान को मदद कर रहे हैं। ईरान ने अब तक मिसाइल वह भी बहुतायत में इजरायल और यूएस बेस पर हमला कर पूरे विश्व के देशों को चौंका दिया है। आज से 4 दिन पूर्व अमेरिका ने पाकिस्तान,तुर्की के माध्यम से 15 विंदु वाली शर्त रखी कि ईरान समर्पण करदे मगर ईरान ने सब शर्तों की बात छोड़ो अपनी तीन शर्तें रखी दी और कहा कि युद्ध में नुक्सान का खर्चा अमेरिका दे, परमाणु हथियारों का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा ।

अब तो ईरान अड़ गया है और डॉनल्ड ट्रंप युद्ध से सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं इसी लिए उन्होंने अपनी समय सीमा 6 अप्रैल तक बड़ा दी है। डॉनल्ड ट्रंप अब अपने देश की राजनीत से परेशान है।उनका लोकप्रिय सेंसेक्स 30 परसेंट पर आ गया।जबकि 27 फरवरी को 63 परसेंट पर था । यूएस कांग्रेस ने युद्ध पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। यद्यपि यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस की बात मांगने के बाध्य नहीं है लेकिन वित्त विभाग कांग्रेस के अधीन है। उल्लेखनीय है कि ईरान में 28 फरवरी के हमले में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमानी सहित 43 लोग मार दिया। अब ईरान की सेना प्रमुख लार्जियानी मारे गए। अब मोजतफा खुमानी सर्वोच्च नेता है ।ईरान में अब तक 3000 लोग मारे गए। यूएस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप ने अब यूक्रेन रूस युद्ध पर हस्तक्षेप कर ने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

संवैधानिक संस्थाओं पर उठते सवालों से कमजोर होता लोकतंत्र

नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51% थी। नेशनल एवरेज 66% था। 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52% थी।

योगेंद्र योगी

देश में समय के साथ लोकतंत्र के परिपक्कव होने के बजाए कमजोर होने की आहट आ रही है। आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात के आरोपों के कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन संस्थाओं के कामकाज के तौर—तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन पर पूरी तरह से सत्तारुढ केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के इशारों पर काम करने करने और विपक्ष के अधिकारों को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों के इस घेरे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और अब मुख्य चुनाव आयुक्त आ चुके हैं।

लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिरला ने ₹पक्षपातपूर्ण व्यवहार₹ दिखाया है और उनका कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका पर चर्चा हुई है और कई बार मेरा नाम लिया गया, मेरे बारे में गंदी बातें कही गईं। उन्होंने कहा कि यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह सदन किसी एक पार्टी का नहीं है, यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं, हमें बोलने से रोक दिया जाता है। ₹₹पिछली बार जब मैंने बात की थी, तब मैंने हमारे प्रधानमंत्री के किए गए समझौतों के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया था। कई बार मुझे बोलने से रोका गया है। पहली बार लोकसभा के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है।

नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51% थी। नेशनल एवरेज 66% था। 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52% थी। नेशनल एवरेज 80% था। 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 43% थी, जबकि नेशनल एवरेज 76% था। उन्होंने कुछ सदस्यों की शिकायतों पर भी बात की कि उन्हें माइक्रोफोन की दिक्कतों की वजह से बोलने नहीं दिया गया। शाह ने कहा कि जो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा या सदन में अनुशासन बनाए नहीं रखेगा, उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाएगा और कहा कि संसद की कार्यवाही इसी तरह चलनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर बिरला के कामकाज के तौर—तरीकों पर उनको हटाने का प्रस्ताव लाकर नाराजगी जताने से पहले राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ पर इसी तरह के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने दिसंबर 2024 में उन्हें पद से हटाने का नोटिस दिया था। विपक्ष का आरोप था कि राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने आरोप लगाया था कि कि धनखड़ एक सरकारी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और एक स्कूल के प्रधानाध्यापक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अक्सर अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं और उन्हें सदन में बोलने से रोकते हैं। खरगे ने यह भी दावा किया था कि सदन में हुई गड़बड़ी के लिए स्वयं श्री धनखड़ जिम्मेदार हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष का सभापति धनखड़ को हटाने का नोटिस खारिज कर दिया था, जिसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन के संचालन का आरोप लगाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। हरिवंश ने यह कहते हुए विपक्ष का नोटिस खारिज कर दिया कि यह तथ्यों से परे है और इसका मकसद केवल प्रचार हासिल करना है। उपसभापति ने कहा था कि धनखड़ के खिलाफ नोटिस अनुचित और त्रुटिपूर्ण है, जिसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है। राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया गठबंधन) के घटक दलों ने सभापति धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस 10 दिसंबर को राज्यसभा के महासचिव को सौंपा था। नोटिस पर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों के 60 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके नेता तिरुचि शिवा और टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी, मुख्य सचेतक जयराम रमेश, वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला तथा कई अन्य सीनियर सदस्यों ने धनखड़ के खिलाफ दिए गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे।

संसद के दोनों सदनों के प्रमुखों के खिलाफ हटाने के प्रयासों के अलावा विपक्षी दलों ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में सौंपा है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को हटाने के विपक्ष के प्रयास सफल नहीं हो सके, उसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग के भी पारित होने की संभावना क्षीण है। विपक्ष के पास महाभियोग पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है। इस तरह के संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को हटाने के लिए एकजुट विपक्ष के प्रयास बेशक सफल नहीं हो पाएं, किन्तु ऐसे प्रयासों से इन पदों की गरिमा कम हुई है। देश में विपक्ष को पूरी तरह से खारिज करके मजबूत लोकतंत्र की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठते सवालों के घेरे में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) का पद भी आ चुका है। इस पद के चयन के लिए कमेटी बनाने की मांग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका लंबित है। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की याचिका में कहा गया है कि अभी कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। इस पद की अहमियत को देखते हुए इसके लिए योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति का चयन जरूरी है इसलिए, सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी के जरिए कैग के चयन का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका है।

टिप्पणी

सशक्त मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर–पोषण निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं सूरजपुर की महिलाएं

आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की नींव सशक्त मानसिकता पर आधारित होती है। दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास व्यक्ति को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सूरजपुर जिले की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इस सोच को व्यवहार में उतारते हुए आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत की है। ये महिलाएं न केवल स्वयं सशक्त बन रही हैं, बल्कि जिले की महिलाओं एवं बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

पोषण आहार (रेडी-टू-ईट या आरटीई) निर्माण संयंत्र सरकार द्वारा संचालित ऐसी इकाइयाँ हैं, जो आंगनवाड़ियों और अन्य योजनाओं के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए पौष्टिक, पहले से तैयार भोजन बनाती हैं, जिसे महिला स्व-सहायता समूहों (स॥त्रह्य) द्वारा चलाया जाता है, जिससे पोषण और महिलाओं का सशक्तिकरण दोनों होता है, जिसमें गेहूं, दालें, और दूध जैसे घटक शामिल होते हैं, जो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

स्वादिष्ट एवं पौष्टिक नमकीन दलिया तथा मीठा शक्ति आहार का निर्माण

जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्काल उपभोग हेतु तैयार पोषण आहार (रेडी टू ईट) निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। इन संयंत्रों में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक नमकीन दलिया तथा मीठा शक्ति आहार का निर्माण किया जा रहा है, जो विटामिन 'ए', विटामिन 'डी', थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरीडॉक्सिन, फोलिक अम्ल, कोबालामिन, लोह तत्व (आयरन), कैल्शियम एवं जिंक जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है।

तीनों संयंत्रों में 32 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से पोषण आहार निर्माण कार्य में संलग्न

जिले प्रशासन द्वारा जिले में कुल 07 पोषण आहार निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए है। यहां वर्तमान में भैयाथान, प्रतापपुर एवं सूरजपुर विकासखंड में तीन संयंत्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इन तीनों संयंत्रों में 32 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से पोषण आहार निर्माण कार्य में संलग्न हैं। निर्मित पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार स्व-सहायता समूहों की महिलाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण में अप्रत्यक्ष किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात है कि पोषण आहार के निर्माण के साथ-साथ उसके वितरण की भी जिम्मेदारी भी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी गई है।

भैयाथान विकासखंड में 15 स्व–सहायता समूह

सूरजपुर विकासखंड में 15 स्व-सहायता समूह तथा प्रतापपुर विकासखंड में 13 स्व-सहायता समूह सक्रिय रूप से वितरण कार्य में अपनी भूमिका निभा रही है। इन समूहों के माध्यम से कुल 430 महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार वितरण कार्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इस योजना से महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। मानसिक रूप से सशक्त ये महिलाएं अब घरेलू कार्यों के साथ-साथ आजीविका से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह पहल न केवल निश्चित रूप से जिले में पोषण स्तर सुधारने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

ब्लॉग

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक भारत की नई उड़ान

सौरभ वार्ष्णेय

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की विकास यात्रा का एक बड़ा आधार बनने जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके माध्यम से प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई मिलेगी। इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक भारत की नई उड़ान माना जा रहा है। इस विकास से प्रदेश का ही नहीं देश का विकास भी संभव हो सकेगा? देश की तरक्की में कम्युनिकेशन यानी यातायात को सुगम बनाना स्वाभाविक ही वह क्षेत्र और देश स्वयं तरक्की के पंख लगा लेता है। आज उसी अध्याय में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को बीमारू छवि से बाहर निकालेगा। प्रदेश की छवि में चार चांद लगेंगे

जैसा की बताया जा रहा है अप्रैल के अंत में फ्लाइट्स शुरू होने के बाद यह देश का पांचवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। चारों फेज का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। 5000 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट का विस्तार होगा। पहले फेज के बाद इस एयरपोर्ट पर यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ होगी। फाइनल फेज पूरी होने के बाद यह 7 करोड़ से अधिक यात्री क्षमता वाला एयरपोर्ट होगा। उड़ानें शुरू होने के बाद तेजी से बढने की उम्मीद है। भविष्य का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की पूरी क्षमता रखता है। इससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को 'बीमारू छवि से बाहर निकालकर 'विकसित प्रदेश की दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। और जब देश का सबसे बड़ा राज्य आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तो स्वाभाविक है कि भारत की समग्र प्रगति भी तेज होगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) का उद्घाटन होने के बाद अब अप्रैल माह के अंत तक उड़ाने शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 65 शहरों के लिए उड़ान शुरू किए जाने का दावा है। पहले चरण में देश के 10 शहरों के लिए सेवा शुरू होगी। शुरुआत में केवल घरेलू और कार्गो उड़ानें ही संचालित होंगी। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यूपी पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वैसे तो देश में एयरपोर्ट अलग-अलग मानकों के आधार पर तय किए जाते हैं। इनमें यात्री क्षमता, क्षेत्रफल और उड़ानों की संख्या शामिल होती है। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं, क्षेत्रफल के लिहाज से हैदराबाद एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। उड़ानों की दृष्टि से सबसे बड़ा एयरपोर्ट

दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसे सबसे बड़ा माना जाएगा। देश के पांच सबसे बड़े एयरपोर्ट होगा।

सबसे पहले, यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार और निवेश के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगा। अभी तक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अत्यधिक दबाव रहता है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट उस दबाव को कम करेगा और क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे निर्यात, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, यह परियोजना रोजगार के विशाल अवसर पैदा करेगी। निर्माण चरण से लेकर संचालन तक लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आसपास के क्षेत्रों—जैसे ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़—में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। तीसरा, यह एयरपोर्ट 'मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का केंद्र बनेगा। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेल नेटवर्क से जुड़कर यह क्षेत्र एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित होगा। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों को अपने उत्पाद देश-विदेश तक पहुंचाने में आसानी होगी।चौथा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने में यह अहम भूमिका निभाएगा। जब वैश्विक कंपनियां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हैं, तो वे निवेश के लिए अधिक इच्छुक होती हैं। इससे 'मेक इन इंडिया और 'आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को मजबूती मिलेगी।

हालांकि, विकास के इस मॉडल में कुछ चुनौतियां भी हैं—जैसे पर्यावरण संतुलन और स्थानीय लोगों के पुनर्वास के मुद्दे। इनका संवेदनशील और संतुलित समाधान जरूरी है, ताकि विकास समावेशी और टिकाऊ बन सके।

उत्तर प्रदेश लंबे समय से अपनी विशाल जनसंख्या, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और सीमित औद्योगिक विस्तार के कारण विकास की चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण न केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाला ऐतिहासिक कदम है।सबसे पहले, यह एयरपोर्ट क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते दबाव को कम करते हुए यह नया हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और निवेश को आकर्षित करेगा। जब दुनिया के बड़े शहरों से सीधी उड़ानें जुड़ेंगी, तो विदेशी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश करना अधिक आसान और लाभदायक होगा।दूसरा महत्वपूर्ण पहलू रोजगार का है। एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। होटल, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी। आसपास के क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों को भी गति मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।तीसरा, यह परियोजना औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों को इस एयरपोर्ट से सीधा लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में यह क्षेत्र तेजी से उभर सकता है। हालांकि, हर बड़े विकास के साथ चुनौतियां भी आती हैं। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास जैसे मुद्दों को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ संभालना होगा। यदि इन पहलुओं की अनदेखी हुई, तो विकास का यह मॉडल असंतुलित हो सकता है। यह कहना अतिश्योक्ति होगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्जागरण का माध्यम बन सकता है। यदि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं, तो यह राज्य को न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर नई पहचान दिला सकता है।

यूपी को 'बीमारू छवि से बाहर निकालेगा

उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लिए विकास का नया इंजन बनने जा रहा है।सबसे बड़ी विशेषता इसकी वृहद क्षमता और चरणबद्ध विस्तार योजना है। पूर्ण रूप से विकसित होने पर यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। शुरुआत में ही इसकी रनवे क्षमता और यात्री संभालने की व्यवस्था इसे भविष्य के दबाव के लिए तैयार बनाती है। अहम विशेषता है इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी। यह एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बड़े हिस्सों को सड़क, रेल और मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी नई गति मिलेगी। अन्य खासियत है इसका ग्रीन और सस्टेनेबल डिजाइन। यह भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने की दिशा में है, जो पूरी तरह से नेट ज़ीरो एमिशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। सोलर एनर्जी, जल संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण इसे भविष्य के एयरपोर्ट्स का मॉडल बनाते हैं। इसके अलावा, यह एयरपोर्ट कार्गो हब के रूप में भी उभरेगा। कृषि, और निर्यात आधारित उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सामाजिक दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में रोजगार सृजन, शहरीकरण और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे आसपास के जिलों का समग्र विकास संभव होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं, बल्कि नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यदि इसे समयबद्ध और संतुलित तरीके से पूरा किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की आर्थिक उड़ान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में समसमायिक विषयों पर चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

पुतला दहन कर जताया गया विरोध, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। गोसाईगंज बाजार के निकट देनवा तालाब के पास प्रतिबंधित पशुओं के काटे जाने की घटना के विरोध में कटका बाजार में आरोपियों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम का नेतृत्व समाजसेवी डॉ. सौरभ मिश्र 'विनम्र' ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियां अत्यंत निंदनीय हैं और इससे समाज की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गोसाईगंज बाजार स्थित ग्राम सभा सिरवारा गौशाला के पीछे जंगल, गणेशपुर कैथोलिक जंगल, ग्राम सभा इटकौली में नदी के किनारे, तेरी गांव में टावर के पास, बैदपुर ककरहा तालाब के आसपास, गोसाईगंज थाना क्षेत्र के कटिहार नदी तट, सरौली जंगल तथा मिश्रौली से फाजिलपुर मार्ग के किनारे नहर के पास आए दिन गौहत्या जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बावजूद गोसाईगंज थाना प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मांग की कि जिन घरों से मांस के अवशेष बरामद हुए हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा आवश्यकतानुसार बुलडोजर कार्रवाई भी की जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर दर्जनों संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और सभी ने एकजुट होकर अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज बुलंद की।

मध्य प्रदेश के सीएम पहुंचे वाराणसी, बाबा दरबार में दर्शन पूजन कर मंदरि की व्यवस्थाओं से हुए अवगत

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार की सुबह वाराणसी पहुंचे। उनका यह दौरा एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए है, जिसमें वे तीन अप्रैल को बरेका मैदान में होने वाले विक्रमोत्सव महानाट्य मंचन की तैयारियों का भी अवलोकन करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।

सुबह जब मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे, तो उनका स्वागत भाजपा नेता शैलेश पांडेय, नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', राकेश सचान, गरिश यादव आदि ने किया। एयरपोर्ट से निकलकर जब वे शहर की ओर बढ़े, तो उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान

उन्होंने वहां दर्शनार्थियों के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी भी ली।

मुख्यमंत्री का यह दौरा वाराणसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर है, बल्कि धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं को भी सुधारने का एक अवसर है। विक्रमोत्सव का आयोजन वाराणसी में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना है, जो स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करें ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान, मुख्यमंत्री ने वहां की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की और कुछ सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा वाराणसी में विकास और सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का वाराणसी दौरा न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है।

यूपी में फिर बावनखेड़ी कांड जैसी साजिश! : परिवार को बेहोश कर प्रेमी संग युवती फरार, पांच अप्रैल को आनी थी बरात

आर्यावर्त संवाददाता

अमरोहा। अमरोहा जिले के चर्चित बावनखेड़ी शबनम कांड की याद दिलाने वाली एक सनसनीखेज घटना थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में सामने आई है। यहां एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ फरार हो गई।

घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने युवती के प्रेमी और उसके दोस्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पांच अप्रैल आनी थी किसान की बेटी की बरात

यह मामला अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। किसान ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। पांच अप्रैल बरात आनी थी। इसके लिए घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। आरोप है कि 29 मार्च की रात करीब आठ बजे गांव के ही रिजवान और उसका दोस्त जुनैद उनके घर पहुंचे। दोनों ने किसान की बेटी के साथ योजना के तहत खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद किसान सहित पूरे परिवार के लोग बेहोश हो गए।

बेहोश लोगों को कराया अस्पताल में भर्ती

रात में जब घर से कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि परिवार के सभी सदस्य अचेत अवस्था में पड़े थे। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई अचंभित रहा गया। ग्रामीणों ने आनन-फानन परिवार के सभी बेहेश सदस्यों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। होश आने पर किसान ने अपनी बेटी को गायब पाया। काफी तलाश के बाद पता चला कि रिजवान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है, जिसमें जुनैद की भूमिका रही। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं।

गौरतलब है कि अमरोहा का बावनखेड़ी शबनम कांड भी इसी तरह की साजिश से जुड़ा था, जिसमें पूरे परिवार को नशीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि, इस मामले में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन घटना ने लोगों को उस खौफनाक वारदात की याद दिला दी है।

सीओ अवधभान भदोरिया ने बताया कि मामले में रिजवान और जुनैद के खिलाफ युवती को बहलाकर ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामला प्रेमप्रसंग से जुड़ा है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

240 गायब मोबाइल साइबर क्राइम सेल ने किया बरामद

जौनपुर। साइबर क्राइम सेल व थानों की साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से 240 गायब मोबाइल कीमत करीब पैंतालीस लाख रूपये के मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया गया सुपुर्द किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव (नोडल साइबर थाना ने पत्रकारों को बताया कि सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से 240 गुमशुदा मोबाइल पैंतालीस लाख रूपय को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया। अब तक कुल 1400 मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया जा चुका है। गुम मोबाइलों के प्रार्थना पत्रों/सीईआईआर पोर्टल के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा पीड़ितों के गुम हुए 240 मोबाइलो में जनपद के भिन्न-भिन्न थाना क्षेत्र से व थानो के साइबर सेल द्वारा बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद आजमगढ, वाराणसी, सुल्तानुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, बलिया, भदोही से मोबाईल फोन बरामद किया गया।

भीषण हादसे में मां-बेटे समेत तीन की मौत, खून से लाल हुई सड़क, शवों के उड़ गए चिथड़े

आर्यावर्त संवाददाता

मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले के अहरौरा-जमुई मार्ग पर रोशनहर के पास मंगलवार की सुबह बाइक से दवा लेने जा रहे मां, बेटे और भतीजे की तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। 100 मीटर तक बाइक ट्रेलर में फंस कर घिसटती रही। जिससे सड़क खून से लाल हो गई। शवों के चिथड़े उड़ गए। वहीं सड़क पर खौफनाक मंजर देख लोगों का दिल कांप उठा। परिवार के तीन लोगों की मौत की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर ही रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी रही।

कैसे हुआ हादसा

अहिरुपुर सोनपुर निवासी अशोक बिंद की पत्नी वेदवती देवी उनका पांच वर्षीय पुत्र अनमोल बिंद तथा भतीजा अनुराग बाइक से घाटमपुर गांव के पास दवा लेने जा रहे थे। रोशनहर के पास पहुंचे कि तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को रौंद दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग तथा ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने अहरौरा-जमुई मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। जाम के कारण मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस किसी तरह ग्रामीणों को समझाने मनाने का प्रयास करती रही। ट्रेलर चालक के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में ले लिया, हालांकि चालक भाग गया है।

रेलवे अंडरपास निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

आर्यावर्त संवाददाता

कूरेभार/सुलतानपुर। ग्राम सभा दखिनवारा पोस्ट कूरेभार, जनपद सुलतानपुर के ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग संख्या 23 सी/ई-2 पर प्रस्तावित अंडरपास निर्माण के विरोध में संयुक्त रूप से माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री विनोद सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित अंडरपास निर्माण से गांव में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है, जिससे दैनिक आवागमन प्रभावित होगा। साथ ही कई घरों के मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने की भी आशंका जताई गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अंडरपास का निर्माण वर्तमान स्थान पर किया जाता है, तो गांव के लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवसर पर रवि सिंह, कुलदीप सिंह और संदीप तिवारी के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को विधायक के समक्ष रखा। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की। विधायक विनोद सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और तत्काल संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि वे इस विषय में माननीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराएंगे तथा जनहित में उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में विधायक द्वारा अपने लेटरहेड पर संबंधित विभाग को पत्र भी प्रेषित किया गया। ग्रामीणों ने विधायक के इस कदम का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई कि जल्द ही इस समस्या का समाधान जनहित में किया जाएगा।

गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सुलतानपुर। सीताकुंड घाट पर गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एक व्यापक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अभिनंदन प्रताप सिंह, जिला परियोजना अधिकारी, डी जी सी, सुल्तानपुर द्वारा किया गया।कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं में स्वच्छता जागरूकता रैली, श्रमदान (सफाई अभियान) तथा गंगा स्वच्छता शपथ शामिल रहे। इस दौरान उपस्थित जनसमूह एवं छात्र-छात्राओं को गंगा नदी की स्वच्छता बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया तथा स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराया गया कार्यक्रम में विशेष रूप से सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर पल्लवी पांडे की सहभागिता रही, जिन्होंने उपस्थित छात्राओं के बीच डस्टबिन का वितरण कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

सिलिंडर के लिए फैली जीजा-साले में रार, बात इतनी बढ़ी ; एजेंसी पर पहुंचकर खोल दिया मोर्चा

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। यूपी के फिरोजाबाद जिले में रसोई गैस की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां किल्लत के बीच आपसी विवाद और साजिशन सिलिंडर हड़पने के अजीबोगरीब मामले भी सामने आए। थाना रामगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एजेंसी पहुंचकर अपने साले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

रामगढ़ क्षेत्र के पीड़ित युवक ने सर्विस रोड स्थित मारुति गैस सर्विस के संचालक प्रकाश निधि गर्ग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। युवक के अनुसार, गैस कनेक्शन उसकी पत्नी के नाम पर है, जिसमें मोबाइल नंबर उसके साले का दर्ज है। साले ने गैस की बुकिंग तो करा दी, लेकिन जब सिलिंडर की डिलिवरी का समय आया, तो उसने अपने नंबर पर आए

ओटीपी को देने से साफ मना कर दिया। साले का तर्क था कि वह इस सिलिंडर का उपभोग खुद करेगा। परेशान जीजा ने अंततः एजेंसी पहुंचकर साले का नंबर हटवाया और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया।

शादी वाले घरों में परेशानी, भटक रहे लोग

मोहल्ला झमैय्या टोला निवासी सलीम ने बताया कि 31 मार्च को उनकी भतीजी शैफी की शादी है। मेहमानों के स्वागत के लिए पकवान बनने हैं, लेकिन सिलिंडर न होने से तैयारियों में बाधा आ रही है।

हनुमान जयंती के भंडारों पर भी संकट

आने वाली हनुमान जयंती को लेकर भी आयोजक चिंतित हैं। शहर में जगह-जगह होने वाले भंडारों के लिए भारी मात्रा में गैस की आवश्यकता होती है। आयोजक अभी से सिलिंडर के इंतजाम के लिए एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्टॉक सीमित होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

केवाईसी और बुकिंग के लिए घंटों इंतजार

शहर की अधिकांश एजेंसियों पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग ई-केवाईसी कराने और बुकिंग स्टेटस जानने के लिए घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं। गोदामों पर पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण एजेंसियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हैं।

राकेश टिकैत की गिरफ्तारी पर मुजफ्फरनगर में भड़का गुस्सा, कार्यकर्ताओं ने घेर लिए थाने, डाल दी चारपाई

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर। किसानों के पैदल मार्च में शामिल होने जा रहे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुलिस ने रोक लिया और थाने ले गई। इसके विरोध में जिलेभर में संगठन के कार्यकर्ताओं ने थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि टिकैत के अलावा संयुक्त मोर्चा के जिन किसानों को पुलिस ने पकड़ा है, उन्हें सम्मान के साथ छोड़ दिया जाना चाहिए।

भुवनेश्वर में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर 22 मार्च से आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी भुवनेश्वर में सोमवार को होने वाले पैदल मार्च में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। भाकियू प्रवक्ता कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया।

पुलिस उन्हें पहले थाने ले गई और इसके बाद गेस्ट हाउस में भेज दिया गया। उधर, टिकैत को रोके जाने की जानकारी मिलते ही कार्यकर्ताओं ने जिले के थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी शहर के सिविल लाइन थाने पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। भाकियू नेता गौरव टिकैत ने कार्यकर्ताओं के साथ भौराकलां थाने में डेरा जमा लिया है। देर रात तक धरना प्रदर्शन जारी है।

इस तरह कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

मीरापुर में भाकियू के नगर अध्यक्ष सुभाषचंद धीमान, शाहपुर में भाकियू के प्रदेश महासचिव सतेंद्र प्रधान एवं जिला उपाध्यक्ष बिजेंद्र बालियान, जानसठ में ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र बालियान के नेतृत्व में पहुंचकर प्रदर्शन किया। मंसूरपुर में जिला महासचिव संजीव राठी, एहसान त्यागी के साथ कार्यकर्ता पहुंचे।

खतौली में की गई नारेबाजी, रात तक डटे

भाकियू के एनसीआर प्रभारी कपिल सोम के साथ कार्यकर्ता खतौली थाने पहुंचे और धरना देकर बैठ गए। देर रात तक यहां पर धरना जारी रहा। सतेंद्र चौहान, सचिन चौधरी, खड़क सिंह सैनी, राहुल अहलावत, प्रवेज प्रधान, मुजम्मिल राना, अंकुश प्रधान मौजूद रहे। उधर, बुढ़ाना और फुगाना में जिला उपाध्यक्ष अनुज बालियान व तहसील अध्यक्ष संजीव पंवार के साथ कार्यकर्ता पहुंचे। सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर अब्दुल राणा, साजिद, गुलफाम व इसरार आदि मौजूद रहे।

चरथावल थाने में डाल ली चारपाई

उड़ीसा में भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में भाकियू कार्यकर्ताओं ने चरथावल थाने में चारपाई डालकर धरना शुरू कर दिया। भाकियू एनसीआर अध्यक्ष विकास शर्मा के संयोजन में क्षेत्र के नाराज किसानों ने कहा कि जब तक भाकियू नेता की रिहाई नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी, पवन त्यागी, नीतू त्यागी, सचिन कुमार, सलमान, सरफराज, रामकुमार आदि मौजूद रहे।

थाने में चढ़ाई भट्ठी, आंदोलन की चेतावनी

जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में पुरकाजी थाने पर धरना दिया। ब्लॉक अध्यक्ष मोनू पंवार, शाह आलम गौड़, दीपक मुखिया, वंश अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने यहां पर भट्ठी चढ़ाई और खाना बनाया।

किसानों की रिहाई तक आंदोलन : गौरव टिकैत

भाकियू नेता गौरव टिकैत ने कहा कि किसानों की रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की नजर भुवनेश्वर पर टिकी हुई है। जरूरत पड़ी तो सड़कों को जाम कर दिया जाएगा।

इशारा मिलते ही सड़कों पर आएंगे : राठी

भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। इशारा मिलते ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है।

बीबीडी में सात दिवसीय विशेष शिविर का भव्य समापन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट-तीन के हेड तुषार वर्मा के संयोजन में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सेमरा में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम बीबीडी ग्रुप की चेयरपर्सन अलका दास गुप्ता, प्रेसिडेंट विराज सागर दास और वाइस प्रेसिडेंट सोनाक्षी दास गुप्ता के संरक्षण में संपन्न हुआ। सात दिनों तक चले इस शिविर में स्वयंसेवकों ने सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉ भूपेन्द्र प्रांत प्रमुख, युवा राष्ट्र के प्रेरणादायी उद्बोधन से हुआ।स्वास्थ्य एवं स्वच्छताः शिविर के दौरान 'स्वच्छ भारत रैली', तंबाकू निषेध अभियान और विशेष 'निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप' का आयोजन किया गया। कौशल विकास, बच्चों के लिए क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी जैसी खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ नृत्य, गायन और चित्रकला के माध्यम से उनकी रचनात्मकता को निखारा गया। स्वयंसेवकों ने आयोजित भव्य भंडारे में भारी संख्या में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने प्रसाद ग्रहण किया। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। समापन अवसर पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा अधिकारी राजेश तिवारी एवं सह प्रचार प्रमुख, सुमित की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों ने स्वयंसेवकों के समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसके श्रीवास्तव, प्रो-वाइस चांसलर डॉ एससी शर्मा, और डीएसडब्ल्यू डॉ. एसएमके रिजवी ने इस पहल को सराहा।

धू-धू कर क्यों जल रहे हैं चार्ज में लगे ई-स्कूटर? ब्लास्ट से बचना है तो आज ही बदल लें ये आदतें

इन दिनों चार्जिंग में लगे ई–स्कूटी में आग लगने कई खबरें सामने आ रही हैं। बहुत से लोग इन खबरों को देखकर घबरा भी हो रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में ई–स्कूटी की बैटरी ब्लास्ट होती है।

देश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों के फटने और आग लगने की बढ़ती घटनाओं ने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में छतरपुर के भेलसी गांव में शनिवार देर रात चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से एक ई-स्कूटी धू-धू कर जल गई। वहीं, शहडोल के धनपुरी में भी शनिवार-रविवार की दरमियानी रात चार्जिंग पर लगी बैटरी में अचानक भीषण धमाका हो गया। इससे पहले इंदौर में हुई एक हृदयविदारक घटना में चार्जिंग के दौरान ईवी में आग लगने से 8 लोग जिंदा जल गए थे।

ये हादसे बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम-आयन बैटरी में 'थर्मल रनवे' की स्थिति कितनी जानलेवा हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि घटिया सेल, खराब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) और चार्जिंग के दौरान बरती गई लापरवाही ही इन घटनाओं की मुख्य जड़ है। इसलिए जो भी उपभोगता इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये लेख जरूर पढ़ना चाहिए।

ई-स्कूटर में ब्लास्ट होने की प्रमुख तकनीकी वजहें

सस्ती ई-स्कूटर कंपनियां लागत कम करने के लिए निम्न स्तर के लिथियम सेल का उपयोग करती हैं, जो भारतीय तापमान को नहीं झेल पाते।

जब बैटरी का एक सेल ओवरहीट होता है, तो वह पास के अन्य सेल्स को भी गर्म कर देता है, जिससे पूरी बैटरी बम की तरह फट सकती है।

बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम तापमान नियंत्रित करना है। अगर यह फेल हो जाए, तो ओवरचार्जिंग से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है।

ब्लास्ट से बचना है तो तुरंत बदलें ये 3 आदतें

स्कूटर को कभी भी सीधी धूप या गर्म जगह पर चार्ज न करें। चार्जिंग के लिए हमेशा छायादार और हवादार जगह का चुनाव करें।

कभी भी सफर से लौटते ही बैटरी को तुरंत चार्ज में लगाएं क्यों वो पहले सी काफी गर्म होती है। ऐसे में कम से कम गाड़ी को 30-45 मिनट ठंडा होने दें, फिर प्लग लगाएं।

कभी भी किसी दूसरी गाड़ी या लोकल मार्केट के सस्ते चार्जर का इस्तेमाल न करें, हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर का ही उपयोग करें।

आग लगने की स्थिति में क्या करें और क्या न करें?

लिथियम बैटरी की आग पर पानी डालना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए केवल 'Class D' या 'Dry Powder' अग्निशामक का ही प्रयोग करें।

अगर संभव हो तो बिना बैटरी को छुए मुख्य स्विच से बिजली का कनेक्शन काट दें।

बैटरी से धुआं निकलने पर उसे किसी बंद कमरे या घर के अंदर न रखें, उसे तुरंत खुले स्थान पर ले जाने की कोशिश करें।

सावधानी ही ईवी सुरक्षा का एकमात्र मंत्र है

इस दौर में इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होनी चाहिए।

छतरपुर, शहडोल और इंदौर जैसी घटनाएं हमें चेतावनी दे रही हैं कि तकनीक का सही ज्ञान ही जीवन बचा सकता है।

हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय ब्रांड के ई-स्कूटर ही खरीदें और समय-समय पर अधिकृत सर्विस सेंटर से बैटरी की हेल्थ चेक कराते रहें।

अगर चार्जिंग के दौरान बैटरी असामान्य रूप से गर्म हो या उससे कोई गंध आए, तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत मेकेनिक से संपर्क करें।

बिना मिट्टी के उगा सकते हैं ये पौधे, खिड़की, दरवाजे और बालकनी की बढ़ जाएगी सुंदरता

पौधे आपके घर की हवा को शुद्ध बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा हरियाली देखकर मन को भी सुकून मिलता है। गर्मी में प्लांट्स घर के टेम्परेचर को भी कम करने में सहायक होते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जो आप घर के अंदर लगा सकते हैं और इनको मिट्टी की जरूरत भी नहीं होती है।

बैंबू प्लांट को फेंगशुई के हिसाब से बहुत ही अच्छा और लकी पौधा माना जाता है तो वहीं ये आपके घर की सुंदरता में भी चार चांद लगाने का काम करता है। आप इसे लिविंग एरिया की टेबल पर रख सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस में भी इसे लगाया जा सकता है। बैंबू प्लांट के लिए जरूरी नहीं है कि आप मिट्टी का यूज करें। इसे आप एक पानी के जार में भी उगा सकते हैं।

मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा एक पॉपुलर इंडोर प्लांट है जिसे आप भी अपने घर में लगा सकते हैं। इसे हल्की धूप पसंद होती है और मिट्टी की जगह आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि पानी में ये थोड़ी धीमी गति से ग्रो करता है। जार का पानी हर 2 से 3 दिनों में बदलते रहें। आप पत्ती की डंडी के साथ इसे उगा सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते में इसमें जड़े आने लगती हैं।

टिलैंडसिया टेक्टोरम एयर प्लांट है, जैसे की इसका नाम है ये हवा की नमी से भी पनप जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो हाई ह्यूमिडिटी में भी ग्रो हो जाएगा। इसके लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है और इसे पत्थर, कांच या लकड़ी के बर्तन में रखकर पानी के साथ उगा सकते हैं। वहीं इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। बस हल्की मिस्टिंग करते रहने से ये ग्रो हो जाते हैं।

सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट को बी आप बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ये हवा को भी शुद्ध करने में हेल्पफुल होता है। आप एक हेल्दी पौधे से गांठ की जगह से तना काटें। बस 6 इंच तक की कल काफी होती है। इसे पानी में डुबोकर रख दें। पानी को 2 से 3 दिन में चेंज करते रहें।

भारतीय घरों में अक्सर मनी प्लांट तो लगा हुआ मिल ही जाती है और सभी को पता है कि मिट्टी के अलावा इसे आप कांच के जार, बोतलों में भी इसे उगा सकते हैं। बस आप 4 से 6 इंच की नोड से कटिंग लेकर इसे पानी में डुबो दें। बस इसका पानी कुछ-कुछ दिनों पर चेंज करते रहें। तकरीबन एक हफ्ते में जड़े निकलने लगती हैं। इसके बाद ये आसान से ग्रो हो जाता है।

फिलोडेंड्रोन (को भी आप बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में उगा सकते हैं। इसमें आप एक हेल्दी तिना को लेकर काट लें और फिर इसे पानी से भरे जार में रख दें। इस जार को आप ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर तेज धूप आती हो लेकिन सीधी न पड़े। कम से कम 4 दिन में जार का पानी चेंज करते रहना जरूरी होता है।

महिलाओं के लिए क्यों खतरनाक है टाइप-2 डायबिटीज? इन गंभीर समस्याओं का बढ़ा देती है खतरा

डायबिटीज की समस्या किसी को भी हो सकती है, पर क्या आप जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में इसका प्रभाव कुछ स्तर पर अलग हो सकता है? महिलाओं में डायबिटीज की समस्या उन्हें कई गंभीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना सकती है।

दुनियाभर में करोड़ों लोग डायबिटीज का शिकार हैं। ब्लड शुगर लेवल का सामान्य से अधिक बना रहना आपके लिए दिक्कतें बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर आपकी HBA1C रिपोर्ट अक्सर 6% से ऊपर बनी रहती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।

डायबिटीज सिर्फ शुगर हाई रहने की बीमारी नहीं है, यह स्थिति शरीर के अन्य कई अंगों की सेहत को भी प्रभावित करने वाली मानी जाती है, यही कारण है कि सभी लोगों को नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराते रहने और इसे नियंत्रित रखने के उपाय करने की सलाह दी जाती है।

वैसे तो डायबिटीज की समस्या किसी को भी हो सकती है, पर क्या आप जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में इसका प्रभाव कुछ स्तर पर अलग हो सकता है? महिलाओं में डायबिटीज की समस्या उन्हें कई गंभीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना देती है।

महिलाओं में बढ़ रही है डायबिटीज की समस्या

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, टाइप-2 डायबिटीज की समस्या वैसे तो पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है। हालांकि, महिलाओं में अक्सर गंभीर जटिलताएं और मृत्यु का जोखिम ज्यादा होता है। इसके अलावा डायबिटीज, विशेषतौर पर ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ स्तर महिलाओं में मूत्र पथ संक्रमण के जोखिम को कई गुना तक बढ़ा देती है। इस तरह के जोखिम को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को आहार-जीवनशैली में सुधार करते हुए मधुमेह को कंट्रोल में रखने पर ध्यान देना चाहिए।

आइए जानते हैं कि मधुमेह के कारण महिलाओं को किस प्रकार की दिक्कतों का जोखिम रहता है?

पीरियड्स पर पड़ता है असर

मासिक धर्म की अवधि के ठीक पहले और उसके दौरान हार्मोन के स्तर में परिवर्तन के कारण ब्लड शुगर के स्तर का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है।

डायबिटीज के कारण आपको हैवी या लंबी अवधि के पीरियड्स की दिक्कत हो सकती है।

इस प्रकार की अनियमितता का शरीर के अन्य अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव होने का खतरा रहता है।

इसी तरह रजोनिवृत्ति के बाद, आपका शरीर कम एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, जो रक्त शर्करा में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का कारण बन सकता है। यह आपके वजन को बढ़ा सकता है, जिससे मधुमेह से संबंधित जटिलताओं के बढ़ने का भी खतरा अधिक होता है। ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है।

क्या आपको भी बार-बार हो रही है यूटीआई?

लगभग सभी महिलाओं को कभी न कभी यूटीआई होने का खतरा रहता है, मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में इसका खतरा अधिक हो सकता है, खासकर यदि रक्त शर्करा का स्तर लगातार अधिक बना रहता हो।

50% से अधिक महिलाओं को उनके जीवनकाल में मूत्र पथ के संक्रमण (यूटीआई) का सामना करना पड़ता है।

मधुमेह इस खतरे को भी बढ़ा देती है। कुछ मामलों में इसके कारण किडनी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है।

बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा

डायबिटीज की शिकार महिलाओं में दिल की बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है।

अध्ययन में पाया गया कि टाइप-2 डायबिटीज वाली महिलाओं में बिना डायबिटीज वालों की तुलना में हृदय संबंधी जटिलताओं के विकसित होने का जोखिम 20 फीसदी अधिक हो सकता है। जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं उन्हें हृदय की सेहत का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए।

दिल की

ईरान युद्ध के बीच सरकार ने केरोसिन की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए नियमों में दी ढील

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान युद्ध के कारण रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच सरकार ने रविवार को केरोसिन की तेज आपूर्ति के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में ढील दी है। यह कदम घरों तक केरोसिन की उपलब्धता जल्दी और आसान बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि खाना पकाने के ईंधन की कमी से राहत मिल सके।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि नए कदमों से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों तक केरोसिन की आपूर्ति आसान और तेज हो सकेगी, ताकि लोग खाना पकाने और रोशनी के लिए इसका उपयोग कर सकें।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन स्टोर करने और घरों को बेचने की अनुमति दी है। हर चयनित पेट्रोल पंप पर अधिकतम 5,000 लीटर केरोसिन रखा जा सकेगा और हर जिले में ऐसे दो पंप तय किए जा सकते हैं।

यह व्यवस्था दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले 'केरोसिन-फ्री' स्थिति थी।

सरकार ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी व्यवस्था 60 दिनों के लिए लागू रहेगी, ताकि तुरंत ईंधन की कमी को दूर किया जा सके। पेट्रोल पंपों के अलावा, राशन दुकानों के जरिए भी केरोसिन वितरित किया जाएगा और राज्यों से ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे एलएनजी की कमी और एलपीजी की संभावित कमी की स्थिति बनी है। इसी को देखते हुए सरकार ने राज्यों को नियमित आपूर्ति के अलावा 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है।

सरकार का कहना है कि एलएनजी आपूर्ति कम होने के कारण केरोसिन को फिर से उपयोग में लाया जा रहा है, ताकि घरों में खाना बनाने और रोशनी के लिए ईंधन की कमी न हो।

मंत्रालय ने यह भी भरोसा दिलाया है कि नियमों में ढील के बावजूद सुरक्षा और निगरानी के सभी मानकों का पालन किया जाएगा, ताकि केरोसिन का गलत इस्तेमाल न हो।

एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को राज्यों को ज्यादा कोयला उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने की सलाह भी दी गई है, ताकि स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ सके।

सोना खरीदने वालों को बड़ा झटका, बाजार खुलते ही 1.46 लाख के पार पहुंची कीमत, चांदी ने भी मारी लंबी छलांग

भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 30 मार्च 2026 को एक बार फिर से भारी उछाल देखने को मिला है। सोने और चांदी की कीमतों में आई इस अचानक तेजी ने खरीदारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (ढ्ढक्चछ्वर) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1 लाख 46 हजार रुपये के आंकड़े को भी पार कर गई है। बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार शाम को यह कीमत काफी नीचे थी, लेकिन नए हफ्ते की शुरुआत के साथ ही सोने ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके साथ ही चांदी के रेट में भी भारी-भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

24 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक के ये हैं आज के भाव

ढ्डड्डद्बड्डत्म्ड्डह्लद्गद्य.ष्शद्व पर सोमवार सुबह जारी किए गए ताजा रेट्स के अनुसार, सोने की हर शुद्धता कैटेगरी में बड़ा उछाल आया है। 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट बढ़कर 1,45,631 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं, आभूषण बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का भाव भी छलांग लगाकर 1,33,935 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। बाजार खुलते ही इन कीमतों में आई तेजी से निवेशकों और आम खरीदारों दोनों में हलचल मच गई है।

एक ही झटके में 3 हजार रुपये तक महंगा हुआ सोना

शुक्रवार शाम के मुकाबले सोमवार सुबह के रेट्स की तुलना करें तो सोने की कीमतों में आग लगी हुई है। 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना सीधे 3,275 रुपये महंगा होकर 1,46,217 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह 23 कैरेट सोना 3,261 रुपये की तेजी के साथ खुला है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसमें 3,000 रुपये का सीधा उछाल आया है। इसके अलावा 750 शुद्धता वाला 18 कैरेट सोना 2,456 रुपये महंगा होकर 1,09,663 रुपये और 585 शुद्धता वाला 14 कैरेट सोना 1,916 रुपये की तेजी के साथ 85,537 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

चांदी ने भी तोड़े रिकॉर्ड, बिना त्रस्न्न के हैं ये सभी रेट

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों ने भी इस बार लंबी छलांग मारी है। 999 शुद्धता वाली चांदी के रेट में एक झटके में 6,345 रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद इसका भाव 2,27,992 रुपये पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर सोमवार से शुक्रवार रोजाना सुबह और शाम को ये रेट अपडेट किए जाते हैं। ग्राहकों के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि ढ्ढक्चछ्वर द्वारा जारी की गई इन सभी कीमतों में जीएसटी (त्रस्न्ज) शामिल नहीं होता है। जब आप बाजार में ज्वैलरी खरीदने जाते हैं, तो आपको इन रेट्स के ऊपर अलग से टैक्स और मेकिंग चार्ज देना होता है।

एनसीएलएटी ने बीएसई की डीमैट खातों को डीफ्रीज करने की याचिका खारिज की

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने बीएसई द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि दिवालियापन अदालतों के पास दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रही कंपनियों के डीमैट खातों को डीफ्रीज करने के आदेश देने का अधिकार है।

अपने आदेश में, एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 60(5) के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई करने और आवश्यक निर्देश पारित करने का स्पष्ट अधिकार है।

इसमें आगे कहा गया कि एनसीएलटी द्वारा पहले पारित आदेश वैध थे और उसकी कानूनी शक्तियों के दायरे में थे।

यह मामला फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज और लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स नामक दो कंपनियों से संबंधित है, जिनके डीमैट खाते बीएसई द्वारा लिस्टिंग शुल्क और अन्य नियामक बकाया का भुगतान न करने के कारण फ्रीज कर दिए गए थे। साथ ही, खाते फ्रीज होने की एक वजह लिस्टिंग नियमों सहित अन्य नियमों का पालन न करना भी था।

इन कंपनियों के मामलों को संभालने वाले रिसॉल्यूशन पेशेवर और लिक्विडेटर ने एनसीएलटी से खातों को डीफ्रीज करने की मांग की थी ताकि दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान शेयरों की बिक्री से धन की वसूली की जा सके।

एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने इससे पहले 2024 और 2025 में पारित अलग-अलग आदेशों में बीएसई को फ्रीज हटाने का निर्देश दिया था। बीएसई ने एनसीएलटी के समक्ष इन निर्देशों को चुनौती दी और तर्क दिया कि प्रतिभूति कानूनों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बनाए गए विनियमों के अंतर्गत आने वाले मामले एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि, एनसीएलएटी ने इस तर्क को खारिज कर दिया। एनसीएलएटी ने कहा कि ऐसे मामलों में डीमैट खातों को डीफ्रीज करने से संबंधित मुद्दे दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से सीधे जुड़े हुए हैं और इसलिए एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि आईबीसी के स्थगन प्रावधानों के तहत ऐसी कार्रवाइयां वर्जित नहीं हैं।

न्यायाधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी विवाद की स्थिति में आईबीसी अन्य कानूनों पर सर्वोपरि है। संहिता की धारा 238 का हवाला देते हुए, इसने कहा कि दिवालियापन या परिसमापन कार्यवाही के दौरान आईबीसी के प्रावधान प्रतिभूति कानूनों सहित अन्य कानूनी ढांचों पर प्रभावी होंगे। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि डीमैट खातों में शेयरों के स्वामित्व पर कोई विवाद नहीं था और कंपनियों द्वारा देय राशि दिवालियापन प्रक्रिया का हिस्सा बन गई थी। इसलिए, एनसीएलटी को ऐसे मामलों से निपटने का पूरा अधिकार था।

ईरान जंग से बढ़ जाएगी महंगाई और धीमी हो जाएगी विकास की रफ्तार, आईएमएफ ने पूरी दुनिया को चेताया

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को अब लगभग एक महीना हो गया है। इस दौरान, कई देशों में महंगाई तेजी से बढ़ी है। ज्यादातर देशों में गैस और तेल की सप्लाई को लेकर भारी उथल-पुथल मची हुई है। इस संघर्ष की वजह से, छोटे देशों की तो बात ही छोड़िए, बड़े-बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी हिल गई हैं। इन सबके बीच, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने अब एक बड़ी चेतावनी जारी की है। IMF ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। आने वाले समय में यह असर और भी गहरा हो सकता है। यह संघर्ष उन कई अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, जो अभी-अभी पिछले संकटों से उबरना शुरू ही हुई थीं।

IMF के अर्थशास्त्रियों टोबियास एड्रियन और जिहाद अजौर द्वारा जारी एक विस्तृत विश्लेषण में कहा है कि यह संघर्ष पहले ही वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। ऊर्जा, खाद्य और वित्तीय बाजारों के माध्यम से इसका असर तेजी से फैल रहा है। इस संकट का सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर देखा जा रहा है। खास तौर पर, होर्मूज स्ट्रेट को लेकर बनी अनिश्चितता ने वैश्विक सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि होर्मूज दुनिया की लगभग 25 से 30 प्रतिशत तेल सप्लाई और लगभग 20 प्रतिशत लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के लिए एक अहम रास्ता है। इसके बंद होने के खतरे से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, और ब्रेंट क्रूड 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है।

विकासशील और गरीब देशों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी

IMF का कहना है कि इस संकट का असर सभी देशों पर एक जैसा नहीं पड़ेगा। विकासशील और गरीब देश, जो ऊर्जा आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन पर इसका सबसे बुरा असर पड़ने की आशंका है। खास तौर पर, एशिया और अफ्रीका के जिन देशों के पास वित्तीय संसाधन सीमित हैं, उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में रुकावटों की वजह से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत, तेल और गैस का निर्यात करने वाले देशों को इस स्थिति से कुछ हद तक फायदा हो सकता है। ऊर्जा संकट के दुष्परिणाम अब खाद्य क्षेत्र में भी दिखाई देने लगे हैं; ईंधन की बढ़ती कीमतों और खाड़ी देशों से उर्वरकों की सप्लाई में रुकावटों की वजह से कृषि उत्पादन की लागत बढ़ रही है। इसका असर भविष्य में फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है और इससे खाद्य महंगाई बढ़ सकती है।

बढ़ती खाद्य कीमतें भी एक बड़ा संकट

IMF ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति उन देशों के लिए विशेष रूप से गंभीर हो सकती है, जहां लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। वास्तव में, कम आय वाले देशों में, परिवार अपने बजट का लगभग 36 प्रतिशत भोजन की चीजों पर खर्च करते हैं, जबकि विकसित देशों में यह आँकड़ा लगभग 9 प्रतिशत है। नतीजतन, भोजन की कीमतों में वृद्धि इन देशों में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। IMF ने कहा कि यदि स्थिति बिगड़ती है, तो कई देशों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि यह संकट वैश्विक स्तर पर महंगाई को फिर से बढ़ा सकता है और आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। कीमतों में वृद्धि की लंबी अवधि महंगाई की उम्मीदों को अस्थिर कर सकती है, जिससे वेतन और कीमतों के बढ़ते चक्र को शुरू होने का जोखिम बढ़ जाता है।

IMF का साफ संदेश

IMF के अनुसार, इस संकट का अंतिम प्रभाव संघर्ष की अवधि पर निर्भर करेगा। अगर यह कम समय तक रहता है, तो नुकसान सीमित हो सकता है। हालांकि, अगर यह लंबे समय तक जारी रहता है या बढ़ता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका लग सकता है। फिलहाल, IMF ने स्पष्ट किया है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपनी आने वाली रिपोर्टों में एक विस्तृत आकलन पेश करेगा। IMF का संदेश साफ है कि यह संकट भले ही क्षेत्रीय हो, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे, और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को पर इसका ज्यादा असर होगा।

मिडिल ईस्ट में 8 भारतीयों की मौत-एक लापता, 55 लाख वापस लौटे, सरकार ने की पुष्टि

नई दिल्ली, एजेंसी। मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में युद्ध का दौर जारी है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जमकर बमबारी हो रही है। इस युद्ध में अब तक जान हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि मिडिल ईस्ट में विभिन्न घटनाओं में अब तक 8 भारतीय नगारिकों की मौत हो गई है। जबकि एक नागरिक अभी लापता है। सरकार का दावा है कि लापता नागरिक का पता लगाया जा रहा है।

मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर महाजन ने कहा कि हाल ही में कुवैत में एक हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। हम मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हालांकि उन्होंने इस मौत के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कुवैत स्थित हमारा दूतावास मृतक के परिजनों के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता कर उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने का प्रयास कर रहा है। महाजन ने दावा करते हुए बताया कि 28 फरवरी से अब तक मिडिल ईस्ट से लगभग 55 लाख यात्री भारत लौट चुके हैं।

संवाद और कूटनीति से खत्म होगा युद्ध

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, युद्ध की स्थिति पर नजर बरकरार है। हम संयम और तनाव कम करने की अपील जारी रखते हैं, और साथ ही संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। पीएम मोदी ने उनके साथ मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रिंस से फोन पर बात करते हुए क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों की भारत की निंदा को भी दोहराया।

भारतीयों के लिए 24 घंटे काम कर रहा दूतावास

विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर महाजन ने कहा कि मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इन देशों में हमारा दूतावास 24 घंटे काम कर रहा है। भारतीय समुदाय लगातार बात की जा रही है। इसके लिए 24×7 हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, नियमित रूप से जरूरी सलाह जारी की जा रही है।

पाकिस्तान में तेल-गैस चोरी करने पर 14 साल की सजा, लगाई जाएगी टेरर की धारा

इस्लामाबाद, एजेंसी। तेल और गैस संकट के बीच पाकिस्तान की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तेल और गैस के अवैध भंडारण और चोरी को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। इसको लेकर सोमवार को नेशनल असेंबली में एक विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के पास होते ही पाकिस्तान में तेल और गैस जमा करना, तस्करी करना और उसे अवैध रूप से रखना गुनाह हो जाएगा। सरकार चाहेगी तो संबंधित शख्स पर टेरर एक्ट भी लगा सकती है।

डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने संसद में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। यह विधेयक तेल और गैस संकट के मद्देनजर किया गया है। सरकार का कहना है कि माफियाओं के साथ मिलकर तेल ठिकानों पर पहले हमला किया जाता है और फिर उसे भंडारण कर उच्च दामों पर बेचा जाता है।

पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों लिया?

पाकिस्तान सरकार का कहना है कि आतंकी पहले पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर माफियाओं के जरिए तेल और गैस बेचते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि तेल और गैस को लेकर पाकिस्तान सरकार ने सख्त कानून लाने का फैसला किया है। सोमवार को बलूचिस्तान में तेल पाइपलान पर हमले की भी खबर आई, जिसके कारण बलूचिस्तान की राजधानी क्वैटा समेत कई इलाकों में सप्लाई बाधित हुई। यह हमला किसने और क्यों किए, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

तेल और गैस के नए कानून में क्या है?

पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार की तरफ से पेश इस विधेयक में कहा गया है-

1- अगर कोई शख्स तेल या गैस की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मुकदमे के तहत शख्स को 14 साल की जेल की सजा होगी। 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

2- इसी तरह अगर कोई व्यक्ति तेल या गैस की तस्करी या भंडारण करते हुए पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। पेट्रोलियम पाइप लाइन पर हमला करने वाले शख्स के खिलाफ भी सख्त सजा का प्रावधान है।

3- नए कानून के मुताबिक तेल और गैस के मामले में आरोपित बनाए गए शख्स को पकड़ने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी शख्स के खिलाफ स्वतः एक्शन ले सकते हैं।

4- पाकिस्तान में आतंक के आरोपितों के साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाता है। आतंक के आरोप में पकड़ने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती है। वहीं आतंकियों को भी 14 साल की मिनिमम सजा दी जाती है।

लखपति दीदी, महिलाओं को 3 हजार रुपये और 2 लाख नौकरियां... असम चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने और 'अरुणोदय' योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सीधी बैंक हस्तांतरण राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वादा किया गया है।

31 वादों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य असम को 'सबसे चमकीला राज्य' बनाना है। उत्तराखंड और गुजरात के नक्शेकदम पर चलते हुए और भाजपा के मुख्य एजेंडे को अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने यूसीसी और कथित 'लव जिहाद' के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया।

सीएम सरमा ने लगाई वादों की झड़ी

उन्होंने कहा कि यूसीसी में संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा और इसे आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं किया जाएगा। सीएम सरमा ने कहा, 'हम असम को सबसे शानदार राज्य बनाना चाहते हैं। हम एक निर्भर राज्य नहीं बनना चाहते। हम देश के राष्ट्र निर्माण में हिस्सा लेना चाहते हैं। संकल्प पत्र में हमने 31 वादे किए हैं। हम असम में यूसीसी लागू करेंगे, जिसमें छठी अनुसूची और एसटी को शामिल नहीं किया जाएगा। हम 'लव जिहाद' के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। हम असम को बाढ़-मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे और पहले दो वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।'

महिलाओं को मिलेगी सौगात

उन्होंने 'लखपति दीदी' योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को लखपति बनाने के लक्ष्य के साथ 25,000 रुपये देने का आश्वासन भी दिया। सीएम ने कहा, 'हम अगले पांच सालों में 2 लाख नौकरियां देंगे। हम 'एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज' बनाना चाहते हैं। हम असम की 40 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य के साथ हर महिला को 25,000 रुपये देना चाहते हैं। हम 'अरुणोदय योजना' के तहत 1250 रुपये की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये करने की कोशिश करेंगे।' इस कार्यक्रम मुख्यमंत्री सरमा के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी उपस्थित थे। दिलीप सैकिया ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य 'सुरक्षित असम, विकसित असम' बनाना है। सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। असम में 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा।

विजय की पार्टी के महासचिव हैं करोड़ों के मालिक : हलफनामे में दिया संपत्ति का पूरा ब्योरा, जानकर हो जाएंगे हैरान

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु में अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (टीवीके) चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी के महासचिव आधव अर्जुना ने चेन्नई की विल्लिवाक्कम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल चल और अचल संपत्ति 197.52 करोड़ रुपये बताई है।

आधव अर्जुना के पास 180.03 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी डेजी अर्जुना के नाम पर 162.14 करोड़ रुपये की चल संपत्ति दर्ज है। साल 2024-25 के लिए आधव ने अपनी कुल कमाई 11.10 करोड़ रुपये दिखाई है। वहीं उनकी पत्नी की कमाई 6.85 करोड़ रुपये रही। आधव अर्जुना ने हलफनामे में बताया कि वह बिजनेस करते हैं। उनके पास 1,691 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 2.29 करोड़ रुपये है। उनकी पत्नी के पास 2,225.62 ग्राम सोना और 24,109.34 ग्राम चांदी है। सोने की कीमत 3.01 करोड़ और चांदी की कीमत 60.27 लाख रुपये है। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास 6.16 करोड़ रुपये के हीरे के गहने भी हैं।

आधव ने अराइज कंस्ट्रक्शन और वॉयस ऑफ कॉमन्स जैसी कई कंपनियों में 2.23 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उनके पास चार गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में 63,332 रुपये की एक स्पोर्ट्स साइकिल भी शामिल है।

अचल संपत्ति के मामले में आधव के पास कोई खेती की जमीन नहीं है। उनके पास 17.49 करोड़ रुपये की कीमत का एक रिहायशी मकान है। उनकी पत्नी के पास 56.43 करोड़ रुपये की खुद खरीदी हुई संपत्ति है। जबकि उनकी विरासत में मिली संपत्ति का मूल्य 26.78 करोड़ रुपये है। डेजी अर्जुना ने भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनियों के शेयरों में 68.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

कर्ज की बात करें तो आधव अर्जुना पर 1.88 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी है। उनकी पत्नी ने बैंकों और अन्य संस्थानों से 26.26 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। टीवीके पार्टी पहली बार इन चुनावों में हिस्सा ले रही है।

विजय वर्मा के जन्मदिन पर फैंस को मिला तोहफा, रिलीज हुआ मटका किंग का टीजर, 17 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो, जो इंडिया का सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है, उसने आज विजय वर्मा के बर्थडे पर उनकी आने वाली ओरिजिनल ड्रामा सीरीज मटका किंग की वर्ल्डवाइड प्रीमियर डेट 17 अप्रैल अनाउंस कर दी है।अभय कोरन्ने की लिखी और नागराज पोपटराव मंजुले की बनाई और डायरेक्ट की गई ये सीरीज 1960 के दशक के बदलते बॉम्बे पर बेस्ड है। ये कहानी एक कॉटन ट्रेडर के इर्द-गिर्द घूमती है जो मटका नाम का एक नया जुआ सिस्टम शुरू करता है और अमीरों के इस शौक को पूरे देश में फैला देता है।

इसे सिद्धार्थ रॉय कपूर, नागराज पोपटराव मंजुले, गार्गी कुलकर्णी, अश्विनी सिदवानी और आशीष आर्यन ने रॉय कपूर फिल्म्स, आटपाट और एसएमआर प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। मटका किंग में विजय वर्मा, कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जादावत और गुलशन ग्रोवर लीड रोल्स में हैं। इनके साथ ही विनीत कुमार सिंह, भरत जाधव, गिरीश कुलकर्णी, जेमी लीवर, किशोर कदम, साइरस साहूकार, अर्पिता सेठिया, संभाजी तांगड़े, इश्तियाक खान, संजीव जोटांगिया और सिमरन अश्विनी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ये सीरीज 17 अप्रैल को भारत और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

मटका किंग की कहानी ब्रिज भट्टी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार विजय वर्मा ने निभाया है। वह 1960 के दशक के बदलते बॉम्बे में अपनी पहचान और इज्जत बनाने की कोशिश में जुटा एक तेज दिमाग और मेहनती कॉटन ट्रेडर है। भीड़भाड़ वाले बाजारों, चॉलों और बदलती पावर डायनेमिक्स के बीच सेट यह कहानी एक महत्वाकांक्षी आइडिया से शुरू होती है, जो धीरे-धीरे अपनी एक अलग पहचान बना लेता है और समाज के हर तबके के लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे-जैसे उम्मीदें और दांव बढ़ते जाते हैं, यह सीरीज महत्वाकांक्षा, ताकत और अपनी जगह बनाने की एक रोमांचक कहानी के रूप में सामने आती है।

प्राइम वीडियो इंडिया के ओरिजिनल्स हेड और डायरेक्टर निखिल मधोक ने कहा, मटका किंग एक ऐसे आदमी की दिलचस्प कहानी है जो बदलते वक्त के साथ हर मुश्किल से लड़कर कामयाब होने की कोशिश करता है, और इसे इस तरह से पेश किया गया है कि दर्शक हैरान रह जाएंगे। ब्रिज भट्टी का मटका किंग बनने का सफर जितना शानदार है, उतना ही एक सबक भी देता है। हम रॉय कपूर फिल्म्स, आटपाट और एसएमआर प्रोडक्शंस के साथ मिलकर इस बोल्ड कहानी को 17 अप्रैल को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं।

मटका किंग के को-प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने बताया, हमें इस सीरीज की ओर जिस चीज ने सबसे ज्यादा खींचा, वो था इसका बड़े स्तर पर बनाया गया अनोखा वर्ल्ड और एक ऐसे इंसान की कहानी, जो तेजी से बदलते समाज में अपनी महत्वाकांक्षा, पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करता है। हालांकि यह कहानी एक खास समय और जगह की है, लेकिन इंसानी सपनों और फैसलों की जो इसमें झलक दिखती है, उससे हर कोई खुद को जोड़ पाएगा। नागराज पोपटराव मंजुले के साथ काम करना काफी सुखद रहा, जिनके काम का मैं हमेशा से कायल रहा हूँ। साथ ही, टैलेंटेड अभय कोरन्ने, जिनके साथ हमने पहले भी सफल काम किया है, उन्होंने कहानी कहने के तरीके में एक अलग क्रिएटिव विजन और सच्चाई भरी है।विजय वर्मा, कृतिका कामरा और गुलशन ग्रोवर जैसे शानदार कलाकारों ने इस सीरीज में जान फूँक दी है। हम इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्राइम वीडियो के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करके बहुत खुश हैं और 17 अप्रैल से मटका किंग को दर्शकों के सामने लाने का इंतजार कर रहे हैं।

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट आगे बढ़ी, अब 17 अप्रैल को पर्दे पर देगी दस्तक

बॉक्स ऑफिस पर होने वाले साल के सबसे बड़े टकराव से बचने के लिए निर्माता एकता कपूर ने बड़ा फैसला लिया है। अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह की मेगा-ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 के साथ सीधे टकराव और बॉक्स ऑफिस प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए एकता ने ये कदम उठाया है, ताकि दोनों फिल्मों के कारोबार पर बुरा असर न पड़े।

एकता की फिल्म भूत बंगला अब 10 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। फिल्म की रिलीज में देरी की खबरों के बीच वैरायटी इंडिया ने भी पुष्टि की है कि इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। । अब इसकी नई रिलीज डेट 17 अप्रैल, 2026 तय की गई है। दरअसल, धुरंधर 2 फिलहाल सिनेमाघरों में राज कर रही है, इसलिए एकता कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं हैं।

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आया है कि बड़े-बड़े हॉलीवुड सितारे भी इसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। फिल्म अभी भी हाउसफुल सिनेमाघरों में चल रही है और लगभग सभी स्क्रीन्स पर इसी का कब्जा है। यहां तक कि हॉलीवुड सुपरस्टार रायन गोसलिंग की बहुप्रतीक्षित फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी, जिसे विशेष रूप से आइमैक्स के लिए फिल्माया गया था, उसे भी भारत में उतनी स्क्रीन्स नहीं मिल पाईं, जितनी उसे जरूरत थी।

इंडस्ट्री के एक सूत्र के अनुसार, भूत बंगला के निर्माताओं को धुरंधर 2 से मुकाबला करने की चुनौतियों का अहसास हो गया था। ये बिजनेस से जुड़ा है बेहतरीन फैसला है, जो न केवल निर्माताओं के लिए, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फायदे का सौदा है। एकता की मां और निर्माता शोभा कपूर ने भी इस फैसले का पूरा समर्थन किया है। इससे पहले यश की फिल्म टॉक्सिक ने भी धुरंधर 2 से टकराने से परहेज किया था।

भूत बंगला अब 17 अप्रैल को रिलीज होगी। पहले ये तारीख सलमान खान की फिल्म मातृभूमिके लिए आरक्षित थी। हालांकि, अभिनेता-गायक प्रशांत तमांग के असामयिक निधन के कारण मातृभूमि की शूटिंग प्रभावित हुई और फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया। इस खाली स्लॉट का फायदा उठाते हुए एकता ने अपनी फिल्म को वहां शिफ्ट कर दिया है। वो अब पूरे 1 हफ्ते बाद फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आएंगी ताकि इसकी कमाई उतनी प्रभावित न हो।

भूत बंगला के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी पूरे 14 साल बाद एक बार फिर पर्दे पर वापसी कर रही है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं।

धुरंधर 2 ने फिर रचा इतिहास, रिकॉर्डतोड़ कमाई के साथ पुष्पा 2 को दी धोबी पछाड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1200 करोड़ पार

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। पहले दिन से ही फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। अब 10वें दिन भी फिल्म ने इतिहास रच दिया है और पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दसवें दिन यानी दूसरे शनिवार 62.85 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म को 44.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली। फिल्म को 18,820 शोज मिले। धुरंधर 2 के दूसरे शनिवार के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं। पर अगर फिल्म ने दूसरे शनिवार को 62.85 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 778.77 करोड़ हो गया है। वहीं फिल्म ने 10 दिनों में दुनियाभर में 1255 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसी के साथ फिल्म हिंदी सिनेमा में दूसरे शनिवार को सबसे कमाने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुष्पा 2 ने दूसरे शनिवार को 46 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब धुरंधर 2 ने इसे पछाड़ दिया है।

फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 43 करोड़ की कमाई की थी। वहीं पहले दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़ का बिजनेस किया। तीसरे दिन फिल्म ने 113 करोड़ कमाए। चौथे दिन फिल्म ने 114.85 करोड़, पांचवें दिन 65 करोड़, छठे दिन 56.60 करोड़, सातवें दिन 48।75 करोड़, आठवें दिन 49.70 करोड़ कमाए। पहले हफ्ते में फिल्म ने 674.17 करोड़ का कलेक्शन किया।

नौवें दिन फिल्म ने 41.75 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं। संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स ने फिल्म में अहम रोल प्ले किया है। ये फिल्म 1,000 करोड़ के घरेलू क्लब की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com